RNI No. DELMUL/2012/47011

05 जुलाई, 2026 रविवार

नई दिल्ली
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 95

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

www.timesofpedia.com Email : timesofpedia@gmail.com

टी20 प्रारूप क्रिकेट का भविष्य, एकदिवसीय का आकर्षण घाट रहा है : आर. अश्विन 07

संक्षिप्त वार्ता

भारत में कार्यरत चीनी बिजली कंपनियों को सरकारी टेंडर भरने की छूट

वेब वार्ता, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भारत-चीन सीमा विवाद और गलवान संघर्ष के बाद लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के बावजूद, देश के बिजली क्षेत्र को लेकर एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक कदम उठाया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भारत में अपनी फैक्ट्रियां चला रहीं चार चीनी बिजली उपकरण निमार्ता कंपनियों को महत्वपूर्ण बिजली परियोजनाओं के सरकारी टेंडर में भाग लेने की अनुमति दे दी है। इन कंपनियों में टीबीईए एनर्जी, नानजिंग इलेक्ट्रिक इंडिया, न्यू नॉर्थईस्ट इलेक्ट्रिक इंडिया और ताईकाई इलेक्ट्रिक इंडिया शामिल हैं। इन्हें सार्वजनिक खरीद नियमों के कड़े प्रावधानों से विशेष छूट प्रदान की गई है, जिसके तहत भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों की कंपनियों के लिए किसी भी सरकारी टेंडर या खरीद प्रक्रिया में बोली लगाने के लिए भारतीय प्राधिकरण से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य था।

राम मंदिर दान मामले में आरोपियों की संपत्ति जांच तेज, पुलिस को मिले अहम रिकॉर्ड

वेब वार्ता, अयोध्या। अयोध्या पुलिस ने राम मंदिर दान प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों के जमीन और बैंक रिकॉर्ड हासिल किए हैं, इसके बाद अपराध से अर्जित संपत्ति (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) की जांच को और तेज किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि राजस्व विभाग से आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों के भूमि रिकॉर्ड मांगे गए थे, जिसमें से अब तक लगभग 20 भूखंडों से संबंधित दस्तावेज पुलिस को मिल चुके हैं। इन दस्तावेजों का गहन सत्यापन हो रहा है।

जांच दल विशेष रूप से यह ध्यान दे रहा हैं कि संबंधित संपत्तियां कब खरीदी गईं और आरोपियों का राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ाव कब हुआ। इन दोनों तारीखों का मिलान जांच के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

पीवी सिंधु लगन और प्रतिभा से रचा ओलंपिक का स्वर्णिम इतिहास

वेब वार्ता, हैदराबाद। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने भारतीय खेल इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराया है। वह ओलंपिक में दो व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली

भारतीय एथलीट हैं, यह एक ऐसा कारनामा है जो उनकी अद्वितीय प्रतिभा और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। 5 जुलाई, 1995 को हैदराबाद में जन्मी सिंधु को बचपन से ही खेलों का माहौल मिला। उनके माता-पिता खुद वॉलीबॉल खिलाड़ी थे, जिन्होंने अपनी बेटी को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हालांकि, सिंधु की प्रेरणा का मुख्य स्रोत 2001 में पुलेला गोपीचंद की ऐतिहासिक इंग्लैंड ओपन जीत बनी, जिसने उन्हें बैडमिंटन का रैकेट थामने के लिए प्रेरित किया। महज 8 साल की उम्र में सिंधु ने बैडमिंटन रैकेट थामा और जल्द ही खेल के प्रति उनकी लगन स्पष्ट हो गई। उन्होंने गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी में दाखिला लिया, जहाँ उन्होंने इस खेल की बारीकियों को सीखा।

एकजुटता का संदेश, टिकट के लिए भारी होड़

दतिया उपचुनाव:गुटबाजी थामने के लिए एक मंच पर आए दिग्विजय और पटवारी

वेब वार्ता, भोपाल

दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले आगामी उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस पार्टी के भीतर मची अंदरूनी खींचतान और गुटबाजी को थामने के साथ-साथ चुनावी रणनीति को धार देने के लिए शनिवार को दतिया के मोटल होटल में कांग्रेस का एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी और खास बात यह रही कि पिछले दिनों हुई तीखी बयानबाजी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी दतिया में एक-साथ पहुंचे। दोनों दिग्गजों का यह साथ आना कार्यकर्ताओं में एकजुटता का संदेश देने की बड़ी कोशिश माना जा रहा है।

दोनों नेता अपने निर्धारित समय से करीब साढ़े तीन घंटे की देरी से कार्यक्रम स्थल पहुंचे, लेकिन उनके आगमन की सूचना मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन स्थल पर भारी संख्या में जुट गए।

टिकट के दावेदारों में भारी होड़ मची

फिलहाल दतिया सीट पर टिकट के दावेदारों में भारी होड़ मची हुई है। दावेदारों में पूर्व विधायक घनश्याम सिंह और पूर्व राज्य मंत्री अवधेश नायक का नाम प्रमुखता से आगे चल रहा है, तो वहीं राजेंद्र भारती के परिवार से भी टिकट की तगड़ी मांग की जा रही है। इनके अलावा जिलाध्यक्ष अशोक दांगी बगदा भी रेस में शामिल हैं। अब देखना होगा कि दिग्गजों की मौजूदगी में होने वाला यह सम्मेलन कांग्रेस की अंदरूनी कलह को शांत करने में कितना कामयाब होता है।

बड़ी संख्या में मौजूद रहे कार्यकर्ता

जैसे ही दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी आयोजन स्थल पर पहुंचे, कार्यकताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और पूरे माहौल में उत्साह छा गया। इस दौरान दोनों ही बड़े नेता मंच के बजाय कार्यकताओं के बीच बैठकर ही कार्यक्रम में शामिल हुए। इस सम्मेलन में जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से आए कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

पीएम मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का किया उद्घाटन

संशोधित उड़ान योजना भी की लॉन्च

वेब वार्ता, जोधपुर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने संशोधित उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना भी लॉन्च की, जिसका उद्देश्य देशभर में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करना और विमानन क्षेत्र के माध्यम से विकास को गति देना है। उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन से पहले नए टर्मिनल भवन का निरीक्षण किया और इसकी आधुनिक सुविधाओं की जानकारी ली। करीब 480 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह नया टर्मिनल 23,000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला है तथा प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है। टर्मिनल में आधुनिक यात्री सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिससे यात्रियों को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। नए टर्मिनल की वास्तुकला राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक और शाही विरासत से प्रेरित है। इसके डिजाइन में पारंपरिक मेहराब, झरोखे और स्थानीय स्थापत्य शैली को आधुनिक वास्तुकला के साथ समाहित किया गया है। भवन में ऊर्जा दक्ष प्रणालियां, जल संरक्षण उपाय और हरित निर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। इसे पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए 5-स्टार जीआरआईएचए रेटिंग के मानकों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। सरकार का मानना है कि नए टर्मिनल के शुरू होने से जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन, व्यापार, निवेश तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। साथ ही क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

निर्धारित किया गया है बजट

इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना की भी शुरूआत की। योजना के तहत अगले दस वर्षों में विमानन क्षेत्र के विस्तार और बेहतर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए 28,840 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत देशभर में मौजूदा अप्रयुक्त हवाई पट्टियों का उपयोग करते हुए 100 नए हवाई अड्डों के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिसके लिए 12,000 करोड़ रुपये से अधिक का बजट निर्धारित किया गया है।

उपमुख्यमंत्री शिंदे की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें ठाणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के

चलते उन्होंने अपने सभी निर्धारित सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से लगातार राजनीतिक व्यस्तताओं और विधानमंडल के चल रहे अधिवेशन के कारण एकनाथ शिंदे पर काम का अत्यधिक दबाव था। इसी दौरान उन्हें बुखार और कमजोरी महसूस होने लगी। इसके बावजूद उन्होंने कुछ निर्धारित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए ठाणे का दौरा किया, लेकिन स्वास्थ्य अधिक खराब होने पर उन्हें कार्यक्रम बीच में ही रद्द करने पड़े। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के बाद शिंदे को घर पर आराम करने के बजाय अस्पताल में भर्ती होकर उपचार कराने की सलाह दी। इसके बाद शुक्रवार देर रात उन्हें ठाणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों का कहना है कि अत्यधिक थकान, वायरल बुखार और कमजोरी के कारण उनकी तबीयत प्रभावित हुई है। हालांकि, उनकी हालत नियंत्रण में है और चिंता की कोई बात नहीं है।

शिंदे की अस्वस्थता का असर राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी पड़ा। ठाणे के गंगूबाई शिंदे हॉल में शुक्रवार को धुले से शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) की उपनेत्री शुभांगी पाटिल के पार्टी प्रवेश का कार्यक्रम प्रस्तावित था। उपमुख्यमंत्री की तबीयत खराब होने के कारण इस कार्यक्रम का समय बदलना पड़ा। बाद में देर रात करीब दो बजे कल्याण से सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे की मौजूदगी में शुभांगी पाटिल ने शिवसेना में प्रवेश किया।

ऋषिकेश में पहली बारिश बनी आफत

देहरादून। मॉनसून की पहली तेज बारिश ने जहां ऋषिकेश को भीषण गर्मी से राहत पहुंचाई, वहीं नगर निगम की लचर व्यवस्थाओं की पोल भी खोल दी। कुछ ही घंटों की बरसात ने शहर के प्रमुख इलाकों को जलमग्न कर दिया, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। सुबह दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, स्कूल-कॉलेज के छात्र और रोजमर्रा के काम से निकलने वाले लोगों को जलभराव के कारण भारी परेशानी झेलनी पड़ी। कई सड़कों पर पानी इतना अधिक जमा हो गया कि गड्ढे और सड़क में फर्क करना मुश्किल था, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया।

आत्मघाती हमले में पाकिस्तान के 30 से अधिक सैनिक मारे गए

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान का ग्वादर जिला शुक्रवार शाम एक भीषण और घातक हमले से दहल उठा, जिसकी जिम्मेदारी प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने ली है। रिपोर्ट के अनुसार, बीएलए ने दावा किया है कि उसके आत्मघाती और अत्याधुनिक हथियारों से लैस लड़ाकों ने ग्वादर के जीवामी स्थित पनवान इलाके में पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड के एक बड़े कैंप पर हमला किया, जिसमें 30 से अधिक पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

बीएलए ने अपने आधिकारिक बयान में बताया कि इस

सबसे खतरनाक और विशिष्ट ऑपरेशन को उनकी मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। संगठन के अनुसार, अताउल्ला बलूच उर्फ अजमल नाम के एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदे एक माजदा ट्रक को कोस्ट गार्ड के भारी सुरक्षा वाले कैंप के भीतर घुसा दिया। स्थानीय समयानुसार शाम करीब 6:32 बजे हुए इस आत्मघाती हमले से एक अत्यंत शक्तिशाली धमाका हुआ, जिसने पूरे कैंप को झकझोर दिया। बीएलए के प्रवक्ता जियांद बलूच ने दावा किया कि इस विस्फोट के कारण कोस्ट गार्ड का मजबूत कैंप पूरी तरह से मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। हमले की पुष्टि और प्रचार के लिए, बीएलए के मीडिया विंग हक्कल ने एक 4 सेकंड का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें कथित तौर पर विस्फोटकों से भरे ट्रक को कैंप में घुसते और उसके तुरंत बाद हुए भीषण विस्फोट को दिखाया गया है।

राम मंदिर के बाद अब बदरीनाथ धाम में भी चढ़ावा चोरी?

बीकेटीसी ने बिठाई जांच, कर्मचारियों को नोटिस जारी

नई दिल्ली। अयोध्या में राम मंदिर से चढ़ावा चोरी मामले में दोषी कौन है इसका खुलासा होता इससे पहले बदरीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी का मामला उजागर हो गया है। यहां मामला सामने आते ही बीकेटीसी ने जांच बैठाते हुए कर्मचारियों को नोटिस थमाकर जवाब मांगा है। अब भक्तों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर मंदिर चढ़ावा चोरी की सक्रिय गैंग पर लगाम कब लगेगी। राम मंदिर में दान चोरी का मामला अभी पूरी तरह सुलझ भी नहीं पाया था कि विश्व प्रसिद्ध बदरीनाथ धाम से चढ़ावे में हेरफेर के चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पत्र तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बदरीनाथ धाम में आने वाले दान और चढ़ावे की रकम में गड़बड़ी की जा रही है। इन बढ़ते आरोपों को गंभीरता से लेते हुए बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने तत्काल प्रभाव से जांच के आदेश दे दिए हैं।

बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि मंदिर समिति ने इन आरोपों को अत्यंत

गंभीरता से लिया है और पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं तथ्यपरक जांच के लिए एक जांच समिति गठित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इसके साथ ही संबंधित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण भी तलब किया गया है। द्विवेदी ने सोशल मीडिया पर किए जा रहे उस दावे का भी खंडन किया, जिसमें एक कर्मचारी को उनका ह्यनिजी सचिवह्न बताया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित व्यक्ति उनका निजी सचिव नहीं, बल्कि बीकेटीसी का एक नियमित सरकारी कर्मचारी है। अध्यक्ष ने दृढ़ता से कहा कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह समिति इस मामले की तह तक जाएगी और सभी तथ्यों को उजागर करेगी। बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी सोहन सिंह रांगड़ ने बताया कि 2 जुलाई से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मामले में मिली शिकायत के आधार पर बदरीनाथ मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई गई है। उन्होंने कहा कि हालांकि, उपलब्ध फुटेज अपेक्षित रूप से स्पष्ट नहीं है, फिर भी मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी जानकारी तत्काल बीकेटीसी अध्यक्ष को दे दी गई।

खामेनेई की अंतिम विदाई में उमड़ा जनसैलाब, भावुक हुए दिग्गज नेता

वेब वार्ता, तेहरान

ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए देश-विदेश से गणमान्य व्यक्तियों और हजारों की संख्या में नागरिकों का सैलाब उमड़ पड़ा है। यह एक ऐसा क्षण है जिसने पूरे ईरान को शोक और भावुकता में डुबो दिया है, और इस दौरान देश के शीर्ष नेताओं की आंखें भी नम हो गईं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलिबाफ को फूट-फूटकर रोते हुए देखा गया, जो देश के सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक व्यक्ति के निधन पर राष्ट्रव्यापी दुख का प्रतीक था।

आयतुल्लाह अली खामेनेई, जिन्होंने पिछले तीन दशकों से ईरान का नेतृत्व किया था, का अंतिम संस्कार 3 से 9 जुलाई तक चलने वाले एक विस्तृत कार्यक्रम के तहत किया गया। उनके अंतिम विदाई समारोह में ईरानी नेताओं के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्य भी शामिल थे, जिन्होंने शोक संतप्त राष्ट्र को अपना गहरा दुख व्यक्त किया। अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी कई देशों के मेहमानों ने ईरान पहुंचकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत सरकार की ओर से बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पबित्र मार्केरिटा ने विशेष प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। खामेनेई का निधन 28 फरवरी को तेहरान पर अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों के पहले दिन हुआ था, जिसने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया था। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इस दुखद अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। तेहरान के राज्यपाल

मोहम्मद सादेग मोतामदियान ने इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजामों की पुष्टि की, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके और शोक का माहौल शांतिपूर्ण बना रहे। इस बीच, ईरान के शक्तिशाली सुरक्षा बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के प्रमुख अहमद वाहिदी ने एक कड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत का बदला लिया जाएगा और ईरान के आत्मसमर्पण का सपना उसके दुश्मनों के लिए एक सपना ही रह जाएगा। वाहिदी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश गहरे शोक में डूबा है, लेकिन साथ ही क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान की भविष्य की दिशा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस अंतिम विदाई समारोह ने न केवल खामेनेई के विशाल प्रभाव को प्रदर्शित किया, बल्कि ईरान के भविष्य और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर पड़ने वाले गहरे प्रभावों को भी रेखांकित किया।

कोल्ड स्टोरेज से सुरक्षित रखी खामेनेई की डेड बॉडी

तेहरान। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का चार महीने के लंबे इंतजार के बाद राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यह देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आयोजन हो सकता है, जिसमें लगभग दो करोड़ शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। खामेनेई (86), जिन्होंने 37 वर्षों तक ईरान के राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक संस्थानों पर सर्वोच्च अधिकार रखा, 28 फरवरी को तेहरान में अपने आवास पर अमेरिका और इजरायल के मिसाइल हमलों के दौरान मारे गए थे। उनका अंतिम संस्कार मूल रूप से मार्च के लिए तय किया गया था, लेकिन अमेरिका और इजरायल के साथ जारी युद्ध के कारण इसे बार-बार टाला गया। ईरानी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि युद्ध से पैदा हुई सुरक्षा स्थिति के कारण यह देरी आवश्यक थी, और यह भी बताया कि खामेनेई के पार्थिव शरीर को धार्मिक आवश्यकताओं के अनुसार पूरे सम्मान के साथ सुरक्षित रखा गया था।

सलमान खुर्शीद और महबूबा भी पहुंची ईरान

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में स्पष्ट किया कि यह प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार का आधिकारिक प्रतिनिधित्व कर रहा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने उपस्थिति दर्ज कराई, जबकि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख महबूबा मुफ्ती के साथ-साथ भारत से गए सिख, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्मगुरुओं ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

संपादकीय

पालमपुर में मॉल रोड

एक हल्की सी शुरूआत भी कारवां बदल देती है और इधर हम सदियां गुजार देते हैं बिना कुछ किए। एक सुखद खबर पालमपुर से आई है। पालमपुर के एसडीएम डा. ओपी यादव ने शहर की तासीर में व्यवस्था बसाने की कोशिश करते हुए मुख्य बाजार को मॉल रोड बनाने का जिम्मा उठा लिया। मॉल रोड यानी वाहन प्रतिबंधित मार्ग। शुक्रवार से रविवार तक शहर का मुख्य बाजार पांच से आठ बजे तक वाहन रहित चलेगा। यह कोई पहली कोशिश नहीं। कई प्रशासनिक अधिकारियों ने अलग-अलग शहरों में मुख्य बाजारों या कुछ अहम सडकों को मॉल रोड बनाने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक दखल, संकीर्णता और नागरिक असहयोग से ऐसा संभव नहीं हो पाया। ऐसे में पालमपुर से हो रहा श्रीगणेश शहरी विकास का अनुशासित पहलू दर्ज कर सकता है। शहरों के बाजारों में पर्यटन की मस्ती अगर कायम करनी है, तो इन्हें वाहन रहित घोषित करना पड़ेगा। मंडी, धर्मशाला, कुल्लू, हमीरपुर, कसौली, डलहौजी व तमाम मंदिरों के प्रमुख बाजारों तथा अहम सडकों को वाहन रहित घोषित करने की जरूरत तब पूरी होगी, जब व्यापार मंडल भी सहयोग करेंगे। करीब डेढ़ दशक पूर्व हमीरपुर के मुख्य बाजार को वाहन रहित मॉल रोड बनाने की मांग उठी, लेकिन व्यापार मंडल नहीं माना। धर्मशाला में ऐसे प्रयास विफल रहे, बल्कि व्यापार मंडल द्वारा वन-वे मानचित्र बनाने की कोशिश में भी जनता आड़े आ गई। वाहन रहित बाजार भले ही समय की मांग हैं, लेकिन ऐसे निर्णयों को अमल में लाने के लिए आवश्यक विकल्पों और नीति-नियमों पर गौर करना होगा।

वाहन रहित बाजारों की परिकल्पना में शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आम नागरिक की सहूलियत से जोड़ना होगा। पालमपुर के बाजार को मॉल रोड घोषित करने के साथ महापार्किंग तथा बाजार तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रिक कार्ट जैसी सुविधा देनी होगी। धार्मिक स्थलों पर बस स्टैंड से मंदिर परिसरों तक रोपवे बिछा कर, वाहन रहित विकल्प तराशे जा सकते हैं। हिमाचल का शहरी पुनर्गठन आवश्यक है और इसके तहत तमाम नगर निगमों के तहत, शहरी विकास योजनाओं का प्रारूप अब अगली सदी के संबोधन में साबित करना होगा। कोलकाता जैसे कई प्राचीन शहरों ने इस लिहाज से कई परियोजनाओं पर काम किए हैं। कोलकाता के बीचों-बीच स्थित कई स्कूल इसलिए अन्यत्र शिफ्ट किए ताकि परिवहन की बाधाएं हटें। कई शहरों में नए ट्रांसपोर्ट कोरिडोर बनाए जा रहे हैं। हिमाचल में परिवहन के विकल्प तथा भौगोलिक स्थिति के अनुरूप रज्जु मार्ग, झूला पुल तथा पैदल भ्रमण कोरिडोर विकसित करने होंगे। इतना ही नहीं, हर शहर की दीर्घकालीन परियोजनाओं में न्यू मार्किट, सब्जी बाजार, कार्यालय परिसर, सामुदायिक मैदान, महापार्किंग स्थल, स्थानीय परिवहन नेटवर्क, टैक्सी स्टैंड, वोल्वो बस स्टैंड, सामुदायिक सेवा स्थल-काउंटर, मनोरंजन पार्क तथा विभिन्न गतिविधियों के जोन स्थापित करने होंगे। बेशक हिमाचल के कुछ शहर नगर निगमों के परिचय से सुसज्जित हो गए हैं, लेकिन इनके परिचय में निखार के लिए नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं, परियोजनाओं और प्राथमिकताओं में बदलाव चाहिए। शहरी विकास की जरूरतों में सार्वजनिक, निजी व वन भूमि के बीच पूलिंग की जरूरत है। कुछ इमारतों को हटाने की जरूरत है, तो वन भूमि का विकास में इस्तेमाल जरूरी है। शहरी विकास के प्रारूप में हर जगह का इतिहास, परंपरा, परिचय तथा विशेषताओं का संरक्षण भी जरूरी है। पालमपुर को बचाने के लिए ट्रैफिक रहित जोन अगर मुख्य बाजार बनता है, तो यह प्रशासनिक आर्डर से नहीं, बल्कि नागरिक समाज, व्यापार मंडल तथा समस्त लोगों के सहयोग से ही संभव होगा।

भूकंप से लोगों को कैसे बचाएंगी सरकारें

अग्नि दुर्घटनाओं की तरह तो नहीं, पर मौटे तौर पर सरकारों को इस बात का अंदाजा है कि देश के किन इलाकों में भूकंप आ सकता है। जिस देश में साफ नजर आने वाले खतरे की नेताओं और सरकारों को परवाह नहीं, उन्हें छिपे हुए अचानक आने वाले खतरों से देश के लोगों को बचाने की क्या परवाह होगी।

वेनेजुएला में एक मिनट के अंदर दो बड़े विनाशकारी भूकंप में करीब दो हजार लोगों की मौत हो गई। इस प्राकृतिक आपदा में करीब 10 हजार लोग घायल हो गए। बगैर किसी चेतावनी के आने वाली भूकंप जैसी आपदाएं सरकारों को चेताती हैं कि पहले से बचाव के उपाय किए जाएं, ताकि कम से कम जानमाल का नुकसान हो सकें। भूकंप का खतरा भारत में भी है। देश के कई हिस्सों में कई बार शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचाई है। सवाल यह है कि पूर्व में आए इन भूकंपों से देश की सरकारों ने कोई सबक सीखा है। क्या देश में ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि भूकंप आने पर कम से कम जानमाल का नुकसान हो। दरअसल भारत के राजनीतिक दलों और सरकारों से किसी भी प्राकृतिक आपदा से पहले और बाद में बचाव की ज्यादा उम्मीदें नहीं की जा सकती हैं। कारण साफ है, केंद्र और राज्यों की सरकारों को सामने स्पष्ट नजर आते हुए खतरों से लोगों को बचाने का कोई इंतजाम नहीं हो, वे भूकंप जैसे छिपे हुए खतरों से कैसे बचाएंगे। दिल्ली के बाद लखनऊ में आग से 15 लोगों की मौत हो गई। ऐसी लाखों इमारतें अकेले उत्तर प्रदेश में हैं, जिनमें आग से बचाने के कोई उपाय नहीं किए गए हैं। जब दिल्ली में आग लगी तभी राज्यों की सरकारों को सतर्क हो जाना चाहिए था। लेकिन सरकारों ने लोगों की जान की परवाह नहीं की।

अगले ही दिन बिहार के मुजफ्फरपुर में आग ने पांच-छह मरीजों को लील लिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के नोएडा और फिर मध्य प्रदेश के इंदौर में आग ने फ्लैट और शोरूम खाक कर दिए। तीन दिन में आग की चार भयानक घटनाओं ने लोगों को डरा दिया है और करीब 26 लोगों की जलकर या काले धुएं की चपेट में आकर मौत हो गई है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर के अनुमानों के अनुसार, वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों के 60 प्रतिशत से अधिक छोटे और मध्यम भवन बिना वैध फायर एनओसी के चल रहे हैं। देश भर में दमकल केंद्रों में 97.5 प्रतिशत, दमकल कर्मियों में 96.2 प्रतिशत और अग्निशमन उपकरणों में लगभग 80 प्रतिशत तक की कमी है। देश के लगभग हर बड़े शहर में सुरक्षा नियमों को दरकिनार किया जा रहा है। यह खतरा ऐसा है, जो साफ दिखाई देता है। इससे बचाव के शत-प्रतिशत इंतजाम भी किए जा सकते हैं। इसके बावजूद राज्यों और केंद्र ने पूर्व में हुए ऐसे हादसों से सबक नहीं सीखा। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है, सामने स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे खतरे से निपटने में सरकारें नाकाम हैं, तो भूंकप जैसी अचानक आने वाली आपदा और उसके भयावह रूप से सरकारें कैसे निपटेंगी। जबकि भूगर्भ वैज्ञानिक साफ चेता चुके हैं कि देश के कितने हिस्सों में कभी भी भीषण भूकंप आ सकता है। पिछले दो दशकों में देश में 10 बड़े भूकंप आए हैं, जिनमें 20000 से अधिक लोगों की जान गई है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी के मुताबिक भारत में करीब 20 करोड़ इमारतें भूकंपीय क्षेत्र 4 और 5 में आती हैं। इनमें से कई इमारतें 30-40 साल पहले बनी थीं और इनमें से कई इमारतें नेशनल बिल्डिंग कोड्स का पालन नहीं करती हैं। भूकंप संभावित क्षेत्रों में जोन-1 में भूकंप आने की आशंका सबसे कम रहती है, वहीं जोन-5 में ज्यादा प्रबल रहती है। दिल्ली-एनसीआर का इलाका सीस्मिक जोन-4 में आता है और यही वजह है कि उत्तर भारत के इस क्षेत्र में सीस्मिक गतिविधियां तेज रहती हैं। भूगर्भ विशेषज्ञों ने भारत के करीब 59 फीसदी भू-भाग को भूकंप संभावित क्षेत्र के रूप में वगीर्कृत किया है।

जानकार सीस्मिक जोन-4 में आने वाले भारत के सभी बड़े शहरों की तुलना में दिल्ली में भूकंप की आशंका ज्यादा बताते हैं। गौरतलब है कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहर सीस्मिक जोन-3 की श्रेणी में आते हैं। जबकि भूगर्भशास्त्री कहते हैं कि दिल्ली की दुविधा यह भी है कि वह हिमालय के निकट है, जो भारत और यूरेशिया जैसी टेक्टॉनिक प्लेटों के मिलने से बना था और इसे धरती के भीतर की प्लेटों में होने वाली हलचल का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नेशनल सेंटर फॉर सिसमोलॉजी के मुताबिक भारत के 29 शहरों पर भूकंप का गंभीर खतरा है। इन शहरों में दिल्ली समेत नौ राज्यों की राजधानियां भी हैं। ये ज्यादातर शहर हिमालय जोन से लगे हैं। हिमालय से लगे शहर दुनिया के उन शहरों में शुमार हैं, जहां भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। दिल्ली, पटना, श्रीनगर, कोहिमा, पुडुच्चेरी, गुवाहाटी, गंगटोक, शिमला, देहरादून, इम्फाल और चंडीगढ़ भूकंपीय क्षेत्र के जोन चार और पांच में हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (आईआईएससी) के मुताबिक ये वो शहर हैं जहां आबादी का घनत्व बहुत सघन है और ये गंगा के मैदानी भाग हैं। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि सिस्मिक जोन-4 में आने वाली राजधानी दिल्ली भूकंप के बड़े झटके से खासा प्रभावित हो सकती है। अगर यहां 7 की तीव्रता वाला भूकंप आया तो दिल्ली की कई सारी इमारतें और घर रेत की तरह भरभराकर गिर जाएंगे। ऐसा इसलिए है, क्योंकि दिल्ली की इमारतों में इस्तेमाल होने वाली निर्माण सामग्री ऐसी है, जो भूकंप के झटकों का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। दिल्ली में मकान बनाने की निर्माण सामग्री ही आफत की सबसे बड़ी वजह है। दिल्ली में 1760 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियां हैं। इन अनधिकृत कॉलोनियों में गैर-इंजीनियरिंग इमारतें बनी हैं, जिनमें भूकंप प्रतिरोध क्षमता शायद ही हो। भूकंप के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील और खतरनाक माने जाने वाले जोन पांच में भारत का पूरा पूर्वोत्तर है। इनमें जम्मू-कश्मीर का कुछ हिस्सा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात के साथ उत्तरी बिहार के कुछ हिस्से और अंडमान निकोबार हैं।

वहीं जम्मू-कश्मीर का कुछ हिस्सा, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात के कुछ हिस्से और महाराष्ट्र का कुछ भाग जोन चार में हैं। गुजरात का भुज 2001 में भयावह तरीके से भूकंप की चपेट में आया था। इस भूकंप में 20 हजार लोग मारे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2025 में आदेश दिया था कि ऐसी सभी इमारतें, जिनमें 100 या उससे अधिक लोग रहते हैं, उनके ऊपर भूकंप-रोधी होने वाली किसी एक श्रेणी का साफ उल्लेख होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश अन्य जनहित के आदेशों की तरह सरकारी फाइलों में दफन हो गया। अग्नि दुर्घटनाओं की तरह तो नहीं, पर मौटे तौर पर सरकारों को इस बात का अंदाजा है कि देश के किन इलाकों में भूकंप आ सकता है। जिस देश में साफ नजर आने वाले खतरे की नेताओं और सरकारों को परवाह नहीं, उन्हें छिपे हुए अचानक आने वाले खतरों से देश के लोगों को बचाने की क्या परवाह होगी। देश में ऐसा एक भी राज्य नहीं है, जहां की किसी भी तरह की इमरातें, अग्नि दुर्घटनाओं से सुरक्षित हों, या उनमें अग्नि दुर्घटना होने पर बचाव के पूरे कानूनी प्रावधान हों, ऐसे में छिपे हुए अचानक आए खतरनाक भूकंप से बचाने के लिए इंतजाम भगवान भरोसे है। होना तो यह चाहिए था कि इतने अग्निकांडों के बाद देश में सरकारों की नींद खुल जानी चाहिए थी। देश के जितने भी व्यावसायिक या निजी इमारतें हैं, उनमें आग से बचाव के इंतजामों की तत्काल जांच की जानी चाहिए थी। आग लगने पर लोगों की जान खतरे में डालने वाले ऐसे भवनों को तत्काल सील किया जाना चाहिए था। इससे भी महत्वपूर्ण जिन विभागों की अग्निशमन के उपायों की जांच करने की जिम्मेदारी है, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए थी। एक के बाद एक अग्नि दुर्घटनाएं होती रहीं, किन्तु सरकारों की नींद नहीं खुली।

योगेंद्र योगी
स्वतंत्र लेखक

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलः पर्यावरण का समाधान या वाहन चालकों से लूट ?

देश में ई20 (20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित) पेट्रोल को बढ़ावा देने की नीति बिना तैयारी के समय के पहले लागू की जा रही है। सरकार का दावा है, इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटेगी। विदेशी मुद्रा की बचत होगी। किसानों को गन्ना और मक्का जैसी फसलों का बेहतर बाजार मूल्य मिलेगा। प्रदूषण में कमी आएगी। सरकार का दावा है, नए फ्लेक्स-फ्यूल और ई20 अनुकूल वाहनों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

दूसरी ओर, वाहन मालिक माइलेज घटने, इंजन की कार्यक्षमता प्रभावित होने, स्टार्टिंग समस्या, वाहन के रबर और पाइपों तथा पुराने वाहनों में तकनीकी खराबियों की शिकायत कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में यह शिकायतें 65 फीसदी तक बढ़ गई हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे अनेक वीडियो सामने आए हैं। इसके बाद भी सरकार दावा कर रही है, भ्रामक जानकारियां भी फैलाई जा रही हैं।

सरकार के अनुसार 1 अप्रैल 2023 के बाद निर्मित अधिकांश नए वाहन ई20 ईंधन के अनुकूल बनाए गए हैं। इससे पहले के करोड़ों वाहनों के मालिकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। कई उपभोक्ता संगठनों के सर्वे में माइलेज कम होने वाहन खराब होने और रखरखाव की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं।

इसी बीच विपक्ष ने भी इस नीति पर सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया जा रहा है। ई20 को पर्याप्त तैयारी के बिना लागू किया गया है। इससे आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए इथेनॉल युक्त ईंधन जबरदस्ती सभी पेट्रोल पंपों के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है। जबकि 2023 के पहले की कोई भी गाड़ी इथेनॉल युक्त पेट्रोल के लिए बनाई ही नहीं गई है। यह सवाल भी उठ रहा है, इथेनॉल पेट्रोल की तुलना में सस्ता है। 20 फीसदी एथेनॉल मिलने के बाद भी तो पेट्रोल की कीमतों में कमी क्यों नहीं की गई है।

विशेषज्ञ बताते हैं, शुद्ध इथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम है, इसलिए 5 से 20 फीसदी तक माइलेज में कमी आना स्वाभाविक है। ई20 ईंधन में माइलेज कम होना स्वाभाविक है। माइलेज वाहन के मॉडल, इंजन तकनीक और ड्राइविंग शैली पर भी निर्भर है।

इस साल बारिश बहुत कम होने की संभावना व्यक्त की जा रही है शुगर केन का उपयोग इथेनॉल में होने के कारण शक्कर के भाव लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं कृषि क्षेत्र में भी इसका बड़ा असर पड़ रहा है ऐसी स्थिति में सरकार का एथेनॉल उत्पादन बढ़ाना खाद्य संकट को भी बढ़ाने वाला साबित होगा। यह आशंका भी व्यक्त की जा रही है।

कुल मिलाकर इथेनॉल मिश्रित ईंधन ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और कृषि अर्थव्यवस्था के लिए अभी एक चुनौती है। इसकी सफलता तभी सुनिश्चित होगी जब पुराने वाहनों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश, पारदर्शी वैज्ञानिक अध्ययन, उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान और कीमतों को लेकर स्पष्ट नीति जब तक सामने नहीं आती है। तब तक सरकार वाहन मालिकों का एक तरह से लूटने और उन्हें परेशानी में डालने का काम कर रही है। पेट्रोल पंपों से ई 20 की अनिवार्य सप्लाई के कारण वाहन मालिकों को जिस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को जल्द ही उनकी चिंताओं का समाधान करना आवश्यक है। देश में दो पहिया और चार पहिया वाहनों की संख्या बड़ी तेजी के साथ बढी है। प्रत्येक परिवार इस समस्या से परेशान है। सरकार को जल्द ही इस पर कोई कदम उठाना चाहिए।

(लेखक-सनत जैन)

वेस्ट टू एनर्जीः ऊर्जा में आत्मनिर्भरता

ऊर्जा किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और विकास की आधारशिला होती है। युद्ध अथवा वैश्विक भू-राजनीतिक संकट के समय ऊर्जा की निर्बाध उपलब्धता खाद्य सुरक्षा और रक्षा आपूर्ति जितनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी वह अपनी तेल और गैस आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में यदि अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो जाएं, तो देश की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

इतिहास साक्षी है कि युद्ध और अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के दौरान ऊर्जा बाजारों में भारी अस्थिरता उत्पन्न होती है। तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि, आपूर्ति में बाधा तथा परिवहन मार्गों के अवरुद्ध होने से ऊर्जा आयात करने वाले देशों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस संदर्भ में वेस्ट टू एनर्जी तकनीक भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता और ऊर्जा संप्रभुता की दिशा में आगे बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बन सकती है। यह तकनीक ठोस अपशिष्ट, कृषि अवशेषों और जैविक कचरे को बिजली, बायोगैस, ऊष्मा तथा जैव-ईंधन में परिवर्तित करती है। इससे एक ओर कचरा प्रबंधन की समस्या का समाधान होता है, वहीं दूसरी ओर घरेलू ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होती है। अपशिष्ट से ऊर्जा : वह प्रक्रिया है जिसमें अनुपयोगी कचरे को उपयोगी ऊर्जा, जैसे बिजली या ऊष्मा में बदला जाता है।

यह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का एक बेहद प्रभावी और आधुनिक तरीका है, जो कचरे के पहाड़ों को कम करने के साथ-साथ हमारी ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा करता है। अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने की मुख्य तकनीकें भस्मीकरण : कचरे को उच्च तापमान पर जलाया जाता है। इससे उत्पन्न ऊष्मा भाप बनाती है, जो टरबाइनों को चलाकर बिजली उत्पन्न करती है। बायोमेथेनेशन : गीले कचरे को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सड़ाकर बायोगैस बनाई जाती है। गैसीकरण : कार्बनिक कचरे को सीमित ऑक्सीजन में गर्म करके सिंथेटिक गैस बनाई जाती है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। वेस्ट टू एनर्जी तकनीक के मुख्य लाभ : लैंडफिल का बोझ कम करना : डब्ल्यूटीई प्लांट नगरपालिका के ठोस कचरे का आयतन लगभग 90 प्रतिशत तक कम कर देते हैं, जिससे शहरों को भारत में हर साल पैदा होने वाले 62 मिलियन टन से अधिक कचरे का प्रबंधन करने में मदद मिलती है। मीथेन उत्सर्जन पर नियंत्रण : जैविक कचरे को लैंडफिल से हटाने से मीथेन गैस निकलना रुकती है। यह सीओ-2 से 28 गुना ज्यादा शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है, जिससे जलवायु पर असर काफी कम होता है। नवीकरणीय बिजली उत्पादन : भारत के चालू 21 डब्ल्यूटीई प्लांट 170 मेगावाट से ज्यादा बिजली बनाते हैं, जो शहरों में विकेंद्रीकृत ऊर्जा आपूर्ति में योगदान देते हैं। एसडीजीज के साथ तालमेल : यह एसडीजी-7 (स्वच्छ ऊर्जा) और एसडीजी-11 (टिकाऊ शहर) का समर्थन करता है, क्योंकि यह शहरी कचरा प्रबंधन को नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के साथ जोड़ता है। भारत में कचरे से ऊर्जा उत्पादन के लिए सरकारी पहल : भारत सरकार ने अपशिष्ट से ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहलें शुरू की हैं। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं वेस्ट टू एनर्जी संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के माध्यम से बायोगैस, संपीड़ित जैव गैस तथा बायोमास आधारित ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सतत योजना और गोबरधन योजना के तहत जैविक अपशिष्ट, कृषि अवशेष एवं गोबर से स्वच्छ ईंधन और ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वेस्ट-टू-वेल्थ मिशन नवाचार एवं तकनीकी समाधानों के माध्यम से अपशिष्ट को उपयोगी संसाधनों एवं ऊर्जा में परिवर्तित करने पर बल देता है। वहीं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 अपशिष्ट के पृथक्करण, प्रसंस्करण और वैज्ञानिक निपटान को अनिवार्य बनाते हैं। ये सभी पहलें मिलकर स्वच्छता, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण तथा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा मिशन : राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति (2022) : ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (2016) : ड्राफ्ट वेस्ट टू एनर्जी नीति (2023)। भारत में अभी 90 प्लस डब्ल्यूटीई प्लांट चल रहे हैं। दिल्ली के ओखला, गाजीपुर और तिमारपुर प्लांट रोज 6500 टन कचरे से 50 प्लस मेगावाट बिजली बनाते हैं। पुणे और इंदौर में बायो-सीएनजी प्लांट गीले कचरे से बसें चला रहे हैं। सरकार स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत 2026 तक 500 से ज्यादा शहरों में डब्ल्यूटीई प्लांट लगाने का लक्ष्य रखती है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जहां देशभर के शहरों ने अपशिष्ट प्रबंधन और स्रोत पृथक्करण के माध्यम से कचरा खत्म करने पर ध्यान केंद्रित किया, वहीं इन प्रयासों के बीच अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य हासिल करना अभी भी बाकी था। हालांकि इस दौरान विभिन्न शहरी स्थानीय निकाय कचरे को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कई तरह के इनोवेशंस पर काम कर रहे थे और इस दिशा में उनके प्रयोग और अनुसंधान कड़ी मशक्कत के साथ निरंतर जारी रहे। अब हम विकसित देशों की तरह कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने की दिशा में अग्रसर हैं। इतना ही नहीं, कुछ शहर तो ऐसे भी हैं, जिन्होंने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में बनने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल प्लांट्स को चलाने में किया। वहीं इस दिशा में सबसे खास उपलब्धि महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ ने हासिल की है, जहां नगर निगम के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में बनी ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। भारत में पशुधन बहुत है। 2025 तक 30.30 करोड़ गाय-भैंस होने का अनुमान है। इनके गोबर से हर दिन 15 करोड़ किलो मीथेन गैस बनाई जा सकती है। साल में 300 दिन काम करके 4500 करोड़ किलो यानी 4.5 करोड़ टन गैस बनेगी। 1 टन से 66 सिलेंडर बनते हैं। इस हिसाब से 297 करोड़ सिलेंडर बनेंगे। भारत में 28 करोड़ परिवार हैं। अगर हर परिवार महीने में 1 सिलेंडर इस्तेमाल करे तो साल में 336 करोड़ सिलेंडर चाहिए। हमारे पास 297 करोड़ का उत्पादन हो सकता है, यानी लगभग पूरा घरेलू खपत का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इसके फायदे : आयात में कमी : विदेशी मुद्रा बचेगी और ऊर्जा में आत्मनिर्भरता आएगी। किसानों की आय भी बढ़ेगी।

अरविंद गुलेरिया
बीडीओ, नारकंडा

आलेख

वेलनेस और डिजिटलीकरण में उलझता प्राथमिक स्वास्थ्य

भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था पिछले एक दशक में अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। डिजिटल तकनीकों का तीव्र विस्तार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (अ१ङ्मू' क्लइी '्रील्ली), टेलीमेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य अभिलेख (ए ीू३१ङ्क्ल्लू ल्ली ' ३ॅ फ्रीङ्ग१ि), स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन और एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म ने स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप को बदलना प्रारम्भ कर दिया है। दूसरी ओर, चिकित्सा विज्ञान भी केवल रोगों के उपचार तक सीमित न रहकर वेलनेस अर्थात समग्र स्वास्थ्य, रोग-निवारण, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, योग और स्वस्थ जीवनशैली पर अधिक बल दे रहा है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (अइ-ल्हड), आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (अइऊट), ई-संजीवनी, अइल्अ डिजिटल स्वास्थ्य आईडी तथा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र जैसी पहलें इसी परिवर्तन की प्रतीक हैं। इन पहलों ने स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में नए अवसर अवश्य प्रदान किए हैं, किंतु एक मूलभूत प्रश्न आज भी प्रासंगिक बना हुआ है—क्या डिजिटल परिवर्तन और वेलनेस-केंद्रित दृष्टिकोण मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थानों का विकल्प बन सकते हैं?

इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है। तकनीक स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक कुशल, पारदर्शी और सुलभ बना सकती है, परंतु वह डॉक्टर, नर्स, दवाएँ, प्रयोगशाला, एम्बुलेंस और सुदृढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थानों का स्थान नहीं ले सकती। स्वास्थ्य सेवा अंततः मानवीय सेवा है, जिसका आधार मजबूत संस्थागत ढाँचा, प्रशिक्षित मानव संसाधन और समुदाय तक पहुँच है। यदि प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था कमजोर होगी, तो सबसे आधुनिक डिजिटल मंच भी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं करा पाएँगे।

भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का आधार उप-स्वास्थ्य केंद्र (रउ), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (ढल्लउ) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (उल्लउ) हैं। यही संस्थान मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, पोषण, परिवार नियोजन, संक्रामक रोग नियंत्रण, गैर-संचारी रोगों की प्रारंभिक पहचान तथा प्राथमिक उपचार जैसी आवश्यक सेवाओं का पहला संपर्क बिंदु हैं। दुर्भाग्य से देश के अनेक ग्रामीण, जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों में ये संस्थान वर्षों से डॉक्टरों, नर्सों, दवाओं, उपकरणों और आधारभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। अनेक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नियमित बिजली, स्वच्छ पेयजल, इंटरनेट, प्रयोगशाला सुविधा और एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित कर देने से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता स्वतः नहीं सुधर सकती।

आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना था। इसके अंतर्गत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के साथ-साथ मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर की प्रारंभिक जाँच, मानसिक स्वास्थ्य, वृद्धजन स्वास्थ्य तथा योग जैसी सेवाओं को भी शामिल किया गया। यह अवधारणा आधुनिक सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण के अनुरूप है, क्योंकि आज अधिकांश बीमारियाँ जीवनशैली से भी जुड़ी हैं। किंतु अनेक स्थानों पर स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र केवल नाम परिवर्तन तक सीमित रह गए हैं। भवन वही हैं, उपकरण वही हैं, मानव संसाधन की कमी भी यथावत है और कई स्थानों पर आवश्यक दवाओं की नियमित उपलब्धता भी नहीं है। यदि संस्थागत क्षमता में समानांतर निवेश नहीं होगा, तो स्वास्थ्य एवं कल्याण केवल नीतिगत शब्द बनकर रह जाएगा।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्त्वाकांक्षी सुधार है। अइल्अ आईडी के माध्यम से प्रत्येक नागरिक का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड तैयार करने, अस्पतालों एवं स्वास्थ्य पेशेवरों का डिजिटल पंजीकरण करने तथा उपचार संबंधी सूचनाओं को एकीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे रोगियों के उपचार का इतिहास सुरक्षित रहेगा, अनावश्यक जाँचों में कमी आएगी, स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता बनी रहेगी तथा नीति-निमार्ताओं को विश्वसनीय आँकड़े उपलब्ध होंगे। यह भविष्य की आवश्यकता भी है। किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड किसी गाँव में डॉक्टर की नियुक्ति नहीं कर सकते, न ही वे दवाओं की अनुपलब्धता या खराब स्वास्थ्य अवसंरचना की समस्या का समाधान कर सकते हैं। यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वयं कार्यक्षम नहीं होंगे, तो डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली केवल सूचना प्रबंधन तक सीमित रह जाएगी।

डिजिटल स्वास्थ्य के समक्ष एक बड़ी चुनौती डिजिटल विभाजन है। भारत में आज भी करोड़ों नागरिकों के पास स्मार्टफोन, गुणवत्तापूर्ण इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता का अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों, जनजातीय इलाकों, पर्वतीय क्षेत्रों, बुजुर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए डिजिटल सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करना आसान नहीं है। यदि स्वास्थ्य सेवाएँ अत्यधिक डिजिटल माध्यमों पर आधारित होंगी, तो समाज का वही वर्ग सबसे अधिक वंचित होगा, जिसे स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे अधिक आवश्यकता है। इसलिए डिजिटलीकरण का उद्देश्य समावेशन होना चाहिए, न कि बहिष्करण।

वेलनेस-केंद्रित दृष्टिकोण आधुनिक स्वास्थ्य नीति का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। स्वस्थ आहार, योग, नियमित व्यायाम, तनाव प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य और नशामुक्त जीवनशैली निश्चित रूप से रोगों की रोकथाम में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किंतु स्वास्थ्य को केवल व्यक्तिगत जीवनशैली का परिणाम मान लेना भी उचित नहीं होगा। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिवेश से गहराई से जुड़ा होता है। गरीबी, कुपोषण, स्वच्छ पेयजल की अनुपलब्धता, खराब स्वच्छता, प्रदूषण, असुरक्षित आवास और शिक्षा का अभाव स्वास्थ्य के ऐसे सामाजिक निर्धारक हैं जिन्हें केवल वेलनेस अभियानों से दूर नहीं किया जा सकता। यदि किसी परिवार के पास पौष्टिक भोजन उपलब्ध नहीं है, तो केवल संतुलित आहार की सलाह उसके स्वास्थ्य में अपेक्षित सुधार नहीं ला सकती। यदि किसी गर्भवती महिला को निकटतम स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़े, तो डिजिटल स्वास्थ्य ऐप उसकी समस्या का समाधान नहीं करेगा।

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में स्वास्थ्य सेवाओं की सफलता का सबसे बड़ा आधार मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य तंत्र ही हो सकता है। कोविड-19 महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी स्वास्थ्य संकट से निपटने में स्थानीय स्वास्थ्य संस्थानों, आशा कार्यकताओं, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकताओं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की भूमिका सबसे महत्त्वपूर्ण होती है। घर-घर सर्वेक्षण, टीकाकरण, संपर्क अनुरेखण, जन-जागरूकता और सामुदायिक निगरानी जैसे कार्य डिजिटल तकनीक की सहायता से अवश्य बेहतर हुए, किंतु उनका वास्तविक क्रियान्वयन जमीनी स्वास्थ्यकर्मियों ने ही किया। इससे यह सिद्ध हुआ कि तकनीक सहायक है, विकल्प नहीं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन लंबे समय से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आधारशिला मानता रहा है। 1978 की अल्मा-अता घोषणा और 2018 की अस्ताना घोषणा दोनों ने इस बात पर बल दिया कि मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था के बिना किसी भी देश में समान, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध नहीं कराई जा सकतीं। भारत की परिस्थितियाँ भी इसी सिद्धांत की पुष्टि करती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का वास्तविक लोकतंत्रीकरण तभी संभव है, जब प्रत्येक नागरिक को अपने निकट गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो।

(डॉ. प्रियंका सौरभ, पीएचडी (राजनीति विज्ञान), कवयित्री एवं सामाजिक चिंतक हैं।)

मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों का लोकार्पण व मुनक नहर का किया निरीक्षण

नई दिल्ली, 04 जुलाई (वेब वार्ता)। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र एवं पीतमपुरा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के साथ-साथ अनेक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पार्कों के सौंदर्यीकरण, आधुनिक जल निकासी व्यवस्था, सीवरेज प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं, सिंचाई इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने अपने दौरे की शुरूआत पीतमपुरा स्थित बीडी-एफडी पार्क में विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों के लोकार्पण से की। इस अवसर पर पार्क में लगाए गए 93 नए इलेक्ट्रिक पोल एवं आधुनिक लाइट व्यवस्था का भी शुभारंभ किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग क्षेत्र में वर्षा जल निकासी एवं सीवरेज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा तैयार की गई विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इनमें डीटी मॉल से सीए ब्लॉक तक दोनों ओर प्रीकास्ट ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण, सीए ब्लॉक से शालीमार विलेज चौक अंडरपास, आरयूबी से जीटी करनाल रोड (आजादपुर मंडी गेट) और शालीमार चौक से डीए ब्लॉक तक आधुनिक जल निकासी प्रणाली का निर्माण शामिल है। साथ ही शालीमार गांव, सहीपुर गांव और आसपास के क्षेत्रों में वर्षों से चली आ रही सीवरेज समस्या के स्थायी समाधान के लिए अतिरिक्त सीवेज पंपिंग स्टेशन तथा उससे संबंधित डिलीवरी लाइन का भी लोकार्पण किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार नागरिकों को जलभराव एवं सीवरेज संबंधी समस्याओं से स्थायी राहत दिलाने के लिए आधुनिक और दीर्घकालिक अवसंरचना विकसित कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मॉनसून के दौरान नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी परियोजनाओं का प्रभावी संचालन एवं नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। इसके बाद उन्होंने एनपी ब्लॉक डिस्पेंसरी का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं, दवाइयों की उपलब्धता, चिकित्सा उपकरणों और नागरिक सुविधाओं की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने इसके बाद सिंघलपुर स्थित मुनक नहर का निरीक्षण किया और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों से जल प्रवाह, नहर के रखरखाव, सफाई व्यवस्था तथा जल प्रबंधन से संबंधित कार्यों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि नहरों एवं जल स्रोतों के संरक्षण और उनकी नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए, जिससे जल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय संतुलन दोनों को सुदृढ़ बनाया जा सके। उन्होंने डीएसईयू कस्तूरबा, पीतमपुरा परिसर का निरीक्षण किया और संस्थान में उपलब्ध शैक्षणिक एवं तकनीकी सुविधाओं, प्रशिक्षण अवसंरचना तथा विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार युवाओं को रोजगारोन्मुख और आधुनिक तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर निवेश कर रही है, जिससे उन्हें उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर अवसर प्राप्त हो सकें।

संक्षिप्त वार्ता

सोने की रामचरितमानस पर केजरीवाल का हमला, बोले- महापाप हुआ

नई दिल्ली, 04 जुलाई (वेब वार्ता)। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा भेंट की गई सोने की रामचरितमानस के कथित रूप से गायब होने के मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे चंदा चोरों का महापाप बताया है। अरविंद केजरीवाल ने सामाजिक माध्यम पर लिखा कि पूर्व केंद्रीय गृह सचिव द्वारा श्रद्धापूर्वक भेंट की गई लगभग 1 किलो सोने की रामचरितमानस भी अब गायब बताई जा रही है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को गंभीर बताते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पूर्व केंद्रीय गृह सचिव एस. लक्ष्मी नारायण ने राम मंदिर में सोने की परत चढ़ी रामचरितमानस भेंट की थी। मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित अनियमितताओं के बीच इसके भी गायब होने का दावा किया जा रहा है।

बताया जा रहा है कि मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित चोरी के मामले की जांच विशेष जांच दल कर रहा है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि कथित रूप से गायब हुए स्वर्ण आभूषणों को पहचान छिपाने के उद्देश्य से गलाया गया या नहीं। वहीं, इस पूरे मामले को लेकर मंदिर ट्रस्ट की ओर से अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

एनडीएमसी सुविधा शिविर में शिकायतें निस्तारित

नई दिल्ली, 04 जुलाई (वेब वार्ता)। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने शनिवार को सुविधा शिविर आयोजित किया। इसमें विभिन्न विभागों से संबंधित 60 शिकायतों का निस्तारण किया गया। परिषद द्वारा उत्तरदायी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित सुशासन स्थापित करने के उद्देश्य से कंवेंशन सेंटर में साढ़े दस से साढ़े बारह बजे के बीच सुविधा शिविर का आयोजन किया गया। इसमें एनडीएमसी के 30 विभागों से 100 से अधिक अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद भी कराया गया।

रोहित लांबा गैंग का गुर्गा गिरफ्तार

नई दिल्ली, 04 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हत्या के प्रयास के मामले में वांटेड रोहित लांबा गिरोह से जुड़े बदमाश आदित्य कुमार (22 वर्ष) को गिरफ्तार किया है।पुलिस ने आरोपी को द्वारका मोड़ के पास उस वक्त गिरफ्तार किया, जब वह अपने एक साथी से मिलने आ रहा था। पुलिस के अनुसार, यह मामला पिछले महीने हुई हिंसक वारदात से जुड़ा है। आरोप है कि आदित्य ने अपने साथियों रोहित लांबा और ऋतिक ठाकुर के साथ मिलकर प्रतिद्वंद्वी गैंग के एक सदस्य पर जानलेवा हमला किया था। इस हमले के बाद फरार चल रहा था। पुलिस ने तब मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी रोहित लांबा और ऋतिक ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया था। सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद आदित्य लगातार दिल्ली-एनसीआर में अपने ठिकाने बदल रहा था और गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा था। आदित्य पिछले कुछ वर्षों से रोहित लांबा के संपर्क में था, जिसने उसे अपने गिरोह में शामिल किया था।

36 वर्ष बाद कर्मचारी की बहाली का आदेश

नई दिल्ली, 04 जुलाई (वेब वार्ता)। उच्च न्यायालय ने दिल्ली फाइनेंशियल कॉरपोरेशन (डीएफसी) को लगभग 36 वर्ष पहले सेवा से हटाए गए एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पुनः सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि किसी कर्मचारी की सेवा औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए समाप्त की गई हो, तो पुनर्बहाली सामान्य नियम है।

अशोक नगर में क्षेत्रवासियों और पहाड़ी समाज से मिले विधायक रविकांत, विकास योजनाओं पर किया संवाद

नई दिल्ली, 04 जुलाई (वेब वार्ता)

त्रिलोकपुरी के विधायक रविकांत ने शनिवार को अशोक नगर स्थित काली बाड़ी मंदिर में स्थानीय निवासी कल्याण संघ के पदाधिकारियों और क्षेत्रवासियों से मुलाकात कर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रस्तावित कार्ययोजना पर भी विचार-विमर्श किया।

रविकांत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सुशासन, विकास और जनकल्याण को नई दिशा मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जनभागीदारी आवश्यक है और इसी उद्देश्य से लगातार क्षेत्रवासियों के बीच संवाद किया जा रहा है। बैठक में त्रिलोकपुरी विधानसभा के प्रभारी सुनील गुप्ता तथा स्थानीय निवासी कल्याण संघ के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। क्षेत्रवासियों ने स्थानीय समस्याओं और विकास संबंधी सुझाव भी विधायक के समक्ष रखे।

इसके बाद रविकांत ने अशोक नगर में पहाड़ी समाज के लोगों से भी भेंट की। उत्तराखंड प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष दिग्पाल कैंथुरा की अध्यक्षता में आयोजित संवाद कार्यक्रम में समाज के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ विभिन्न सामाजिक और विकास संबंधी विषयों पर चर्चा की गई।

इस अवसर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं, सुशासन और विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई। विधायक ने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग का सहयोग और विश्वास ही क्षेत्र के विकास की सबसे बड़ी शक्ति है। कार्यक्रम में त्रिलोकपुरी विधानसभा के प्रभारी सुनील गुप्ता भी उपस्थित रहे। रविकांत ने पहाड़ी समाज के लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज का स्नेह, सहयोग और समर्थन उन्हें जनसेवा के लिए निरंतर प्रेरित करता है।

मानहानि मामले में मंत्री प्रवेश वर्मा ने बयान दर्ज कराए

नई दिल्ली, 04 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आप नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर मानहानि मामले में शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 15 जुलाई तय करते हुए गवाहों के बयान दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत में वर्मा ने कहा कि मई 2026 में सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए, जिससे उनकी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा। यह मामला एक निजी स्कूल से जुड़े एक घटनाक्रम पर की गई सोशल मीडिया टिप्पणी से संबंधित है। वर्मा ने आरोप लगाया कि सौरभ ने उन्हें एक स्कूल से जुड़े पॉक्सो मामले में आरोपी की मदद करने वाला बताया और यह भी कहा कि उस स्कूल का ट्रस्ट उनके नियंत्रण में है तथा उन्होंने ही ट्रस्ट में एक व्यक्ति की नियुक्ति की है। वर्मा ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है।

दिल्ली में वर्षा का दौर जारी, मौसम विभाग का पीला सतर्कता संकेत

नई दिल्ली, 04 जुलाई (वेब वार्ता)। राजधानी दिल्ली में उमस भरे मौसम के बीच शनिवार को कई क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी कुछ घंटों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा, तेज हवाओं और आकाशीय बिजली की संभावना को देखते हुए पीला सतर्कता संकेत जारी किया है।

मौसम विभाग के अनुसार राजधानी के अनेक क्षेत्रों में अगले कुछ घंटों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इस दौरान गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ स्थानों पर हवा की गति बढ़कर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में शनिवार को न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक रहा। वहीं अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सुबह के समय वायु में आर्द्रता का स्तर 77 प्रतिशत दर्ज किया गया, जिसके कारण दिनभर उमस बनी रही।

मौसम विभाग का अनुमान है कि राजधानी में 9 जुलाई तक वर्षा का सिलसिला जारी रह सकता है। इस अवधि में बीच-बीच में हल्की और मध्यम वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने की भी संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आने और मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बने रहने की उम्मीद है।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार रविवार से वर्षा की गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है। बादल छाए रहने के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं का प्रभाव भी बढ़ सकता है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार दक्षिण-पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, मध्य दिल्ली, उत्तर-पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली, दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली तथा उत्तरी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा और तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है।

नवनियुक्त जिला पदाधिकारियों का स्वागत एवं सम्मान, संगठन को मजबूत बनाने पर जोर

नई दिल्ली, 04 जुलाई (वेब वार्ता)

भारतीय जनता पार्टी के मयूर विहार जिला उपाध्यक्ष एवं अधिवक्ता मोहित शर्मा ने बताया कि नगर निगम शाहदरा दक्षिण क्षेत्र के अध्यक्ष राम किशोर शर्मा ने पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के नवनियुक्त जिला पदाधिकारियों का अपने कार्यालय में आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया।

कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मयूर विहार जिला प्रभारी श्रीमती योगिता सिंह, सह-प्रभारी नरेश कुमार वशिष्ठ, जिला अध्यक्ष विजेंद्र धामा सहित जिले के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कार्यों को मिलेगी नई ऊर्जा

इस अवसर पर संगठन को और अधिक सशक्त बनाने, कार्यकताओं के साथ समन्वय बढ़ाने तथा जनसेवा को प्राथमिकता देने पर विचार-विमर्श किया गया। वरिष्ठ नेताओं ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को संगठन की नीतियों और जनहित के कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ाने का आह्वान किया। मोहित शर्मा ने नगर निगम शाहदरा दक्षिण क्षेत्र के अध्यक्ष राम किशोर शर्मा का आत्मीय स्वागत एवं सम्मान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वरिष्ठ नेतृत्व का मार्गदर्शन संगठन के कार्यकताओं के लिए प्रेरणादायी है और इससे संगठनात्मक कार्यों को नई ऊर्जा मिलेगी।

हर्ष मल्होत्रा ने विकासपुरी स्थित श्री राम हॉस्पिटल में हार्ट सेंटर का किया उद्घाटन

नई दिल्ली, 04 जुलाई (वेब वार्ता)

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने शनिवार को विकासपुरी स्थित श्री राम हॉस्पिटल में श्री राम हार्ट सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सांसद कमलजीत सहरावत भी मौजूद रहीं। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने एक काम देश के नाम अभियान के अंतर्गत आयोजित 400वें निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में सहभागिता की।

इस अवसर पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में यह पहल समाज के प्रति सेवा, संवेदनशीलता और जनकल्याण की उत्कृष्ट मिसाल है। ऐसे प्रयास गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ स्वास्थ्य सुविधाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण

भूमिका निभाते हैं। सांसद कमलजीत सहरावत ने समाज की सेवा और जनकल्याण के लिए समर्पित इस सराहनीय पहल के लिए हॉस्पिटल के डायरेक्टर पंकज नागपाल और पंकज सिंघल को बधाई एवं शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि स्वस्थ भारत के निर्माण की दिशा में ऐसे प्रयास निश्चित रूप से प्रेरणादायी हैं। इस अवसर पर हॉस्पिटल के निदेशक पंकज नागपाल एवं पंकज सिंघल, भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश बब्बर, डीडीए सदस्य राजीव बब्बर, निगम पार्षद हरीश ओबरॉय सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे।

6-7 जुलाई को कई इलाकों में नहीं आएगा पानी

नई दिल्ली (वेब वार्ता)

राजधानी के कई क्षेत्रों में 6 जुलाई सुबह 10 बजे से 7 जुलाई शाम 4 बजे तक पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि खिजराबाद गांव के पास नई जल पाइपलाइन को जोड़ने के कार्य के कारण यह अस्थायी व्यवधान रहेगा।

जल बोर्ड के अनुसार, इस दौरान सराय काले खां, आश्रम, सिद्धार्थ नगर, सनलाइट कॉलोनी, जसोला, जसोला विहार, सरिता विहार, बादरपुर, साकेत, मालवीय नगर, चिराग दिल्ली, हौज खास, वसंत कुंज, गुलमोहर पार्क, खेल गांव, सीआर पार्क और आसपास के कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित हो सकती है। बोर्ड ने नागरिकों से अपील की है कि वे पहले से अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पानी का भंडारण कर लें। किसी भी आपात स्थिति में जल आपूर्ति से संबंधित सहायता के लिए 1916 सहित क्षेत्रीय सहायता नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। जल बोर्ड ने कहा है कि पाइपलाइन जोड़ने का कार्य पूरा होते ही प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी।

दिल्ली में कथित स्वास्थ्य घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी का सरकार पर हमला

नई दिल्ली, 04 जुलाई (वेब वार्ता)। आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने दिल्ली सरकार पर स्वास्थ्य विभाग में कथित 650 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि दवाओं, एक्स-रे मशीनों, बेडशीट, ओआरएस पैकेट और अन्य चिकित्सा उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर वित्तीय कमियां पाई गई है।

आप नेता संजय सिंह ने शनिवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में सरकार पर आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग में नियमों की अनदेखी कर नियुक्तियां की गईं और इसके बाद खरीद प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं को

अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि 'भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो' (एसीबी) की एफआईआर में भी कई गंभीर आरोप दर्ज हैं और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

संजय सिंह ने कहा कि पोर्टेबल एक्स-रे मशीनों की खरीद के लिए पहले कम संख्या में टेंडर जारी किया गया, लेकिन बाद में मशीनों की संख्या कई गुना बढ़ा दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन मशीनों की कीमत अन्य संस्थानों में लगभग एक लाख रुपये प्रति यूनिट थी, उन्हें दिल्ली सरकार ने लगभग तीन लाख रुपये प्रति यूनिट की दर से खरीदा, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।

उन्होंने चादर खरीद को लेकर भी आरोप लगाया कि अस्पतालों के प्रत्येक बेड के लिए आवश्यकता से कहीं अधिक बेडशीट खरीदी गईं और उनकी कीमत भी बाजार दर से कई गुना अधिक चुकाई गई। साथ ही उन्होंने कहा कि ओआरएस पैकेट के घोल जो को 15 रुपये मिलते है एक करोड़ रुपये का सामान 7.5 करोड़ रुपये में खरीदा और दवाओं की खरीद में भी कथित रूप से अधिक कीमत पर खरीदारी कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया।

संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बड़ी मात्रा में दवाओं की खरीद स्थानीय केमिस्टों से कराई गई, जबकि थोक खरीद के माध्यम से इन्हें काफी कम कीमत पर खरीदा जा सकता था। उन्होंने कहा कि इस मामले में राजनीतिक जवाबदेही तय नहीं की जा रही है, अब तक किसी मंत्री के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हुई है। संजय सिंह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह तथा संबंधित अधिकारियों से पूछताछ और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

अवैध कब्जों पर सख्ती, राजधानी के विकास का नया खाका तैयार

नई दिल्ली, 04 जुलाई (वेब वार्ता)। राजधानी में अवैध कब्जों और अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध अब और कठोर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद की बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अवैध कब्जों और अनधिकृत निर्माण के मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए तथा इनके विरुद्ध 'शून्य सहनशीलता' की नीति अपनाते हुए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही आधुनिक तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था विकसित करने पर भी बल दिया गया, जिससे ऐसे मामलों की समय रहते पहचान कर प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

बैठक में राजधानी के भावी विकास की रूपरेखा, नागरिक सुविधाओं के विस्तार, शहरी नियोजन तथा आधारभूत ढांचे को अधिक सुदृढ़ बनाने पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि दिल्ली का विकास समावेशी, टिकाऊ और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बदलती शहरी चुनौतियों का समाधान पारदर्शी व्यवस्था, आधुनिक तकनीक और विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों से ही संभव है। बैठक के दौरान राजधानी की प्रमुख समस्याओं में आवास की कमी, अनधिकृत कॉलोनियां, झुग्गी-बस्तियां, यातायात जाम, प्रदूषण तथा जल उपलब्धता को प्राथमिकता वाले विषयों के रूप में चिन्हित किया गया। इन सभी चुनौतियों के समाधान के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार करने पर सहमति बनी।

प्रस्तुत दृष्टि-पत्र के अनुसार राजधानी में मुख्य विकास और पुनर्विकास क्षेत्रों के अंतर्गत लगभग 1400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त भूमिगत रेल मार्गों के आसपास लगभग 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में परिवहन आधारित विकास को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा गया है। भूमि समेकन नीति के अंतर्गत लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का विकास किया जाएगा, जबकि यमुना तट क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को प्रस्तावित किया गया है। नई विकास योजना में नियोजित आवासीय विस्तार के साथ-साथ अनधिकृत कॉलोनियों, झुग्गी-बस्तियों तथा पुरानी दिल्ली के पुनर्विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके अलावा शहरी बाढ़, अत्यधिक ताप प्रभाव, जर्जर होती ऐतिहासिक धरोहरों तथा जल संकट जैसी समस्याओं के समाधान के लिए भी व्यापक कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से विभिन्न परिवहन साधनों के बेहतर समन्वय तथा अंतिम चरण तक सुविधाजनक संपर्क व्यवस्था विकसित करने पर भी विशेष चर्चा हुई। इसके माध्यम से राजधानी में यातायात जाम की समस्या को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। दृष्टि-पत्र में हरित क्षेत्र बढ़ाने, जल संरक्षण को मजबूत करने, सुरक्षित सड़कों का निर्माण, माल परिवहन सुविधाओं का विकास तथा प्रमुख व्यावसायिक बाजारों के पुनर्विकास जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी शामिल किए गए हैं।

तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि राजधानी को अधिक हरित, रहने योग्य, आर्थिक रूप से सशक्त और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार शहर बनाने के उद्देश्य से सभी संबंधित विभागों और संस्थाओं को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, समयबद्धता और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

संक्षिप्त वार्ता

मिशन 'सेफ फ्यूचर' अभियान में 21 वाहनों का हुआ चालान, 3 हुए सीज

वेब वार्ता, देहरादून

वेब वार्ता, कानपुर। उत्तर प्रदेश सरकार अब स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त हो गई है। परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन के निर्देश पर पूरे प्रदेश में 1 से 15 जुलाई 2026 तक 'मिशन सेफ फ्यूचर' अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत आरटीओ प्रवर्तन राहुल श्रीवास्तव प्रवर्तन टीम व पुलिस टीम के साथ सड़क पर उतरे और खुद कमान संभाली। मिशन सेफ फ्यूचर इस अभियान के तहत 21 वाहनों का चालान किया तो वहीं 3 वाहनों पर सीज की कार्यवाही की गई।

कानपुर मंडल आरटीओ प्रवर्तन राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि यूपी सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किये है, कि जो भी स्कूल वाहन अनफिट और बिना परमिट दौड़ रहे उन स्कूली वाहनों के खिलाफ बड़े स्तर पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में शनिवार को पनकी में अभियान चला कर 21 वाहनों पर चालान कि कार्यवाही की गई तो वही 3 वाहनों को सीज किया गया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 7 दिनों की मोहलत मंडल के अंतर्गत सभी स्कूल प्रबंधकों को दी गई है,की वह अपने वाहन की फिटनेस और परमिट को वैद्य करा ले, नहीं तो उसके बाद चालान की कार्यवाही के साथ सीज की कार्यवाही भी तुरंत की जाएगी। इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मैनेजमेंट पोर्टल' के डेटा के अनुसार, प्रदेश में हजारों वाहनों की फिटनेस और परमिट वैध नहीं हैं। ऐसे सभी स्कूल प्रबंधकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। साथ ही फोन और व्यक्तिगत रूप से भी सचेत किया जा रहा है। प्रवर्तन कार्यवाही में एआरटीओ प्रवर्तन तृतीय सोम लता यादव, पीटीओ दीपक सिंह व पनकी पुलिस मौजूद रही।

मेडिकल कॉलेज की निमार्णाधीन परियोजनाओं पर जिलाधिकारी सख्त

देवरिया, वेब वार्ता

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज की निमार्णाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्थाओं को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने सभी लंबित निर्माण कार्यों को एक सप्ताह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए और चेतावनी दी। निर्धारित समयसीमा में कार्य पूरा न होने पर संबंधित संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने निमार्णाधीन ट्रॉमा सेंटर में बिजली, पेयजल, ऑक्सीजन पाइपलाइन सहित सभी आवश्यक सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराकर एक सप्ताह के भीतर हैंडओवर करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ट्रॉमा सेंटर का संचालन हर हाल में शीघ्र शुरू होना चाहिए और अब किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा बैठक में उन्होंने क्रिटिकल केयर यूनिट, नर्सिंग कॉलेज सहित अन्य सभी निमार्णाधीन परियोजनाओं में तेजी लाकर उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को आवश्यक मैनपावर, उपकरण और अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा।

अपर कृषि निदेशक ने खरीफ तैयारियों, प्राकृतिक खेती और किसान योजनाओं की प्रगति का किया विस्तृत निरीक्षण

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई प्रदेश की कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा खरीफ सीजन की तैयारियों का जायजा लेने के उद्देश्य से अपर कृषि निदेशक (प्रसार) उत्तर प्रदेश डॉ. कनीज फातिमा एवं संयुक्त कृषि निदेशक डॉ. अजय कृष्णा ने शनिवार को हरदोई जनपद का भ्रमण कर कृषि विभाग की विभिन्न इकाइयों का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर किसानों के हित में संचालित योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की और आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

भ्रमण के दौरान अधिकारियों ने सबसे पहले कृषि फार्म पर बोई गई खरीफ फसलों का निरीक्षण किया। उन्होंने फसलों की स्थिति, उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनाई जा रही तकनीकों तथा खेतों में किए जा रहे प्रयोगों की जानकारी प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला का निरीक्षण कर मिट्टी परीक्षण की प्रक्रिया, किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और प्रयोगशाला की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया। साथ ही आईपीएम (समेकित कीट प्रबंधन) लैब का निरीक्षण कर जैविक एवं वैज्ञानिक तरीके से फसलों की सुरक्षा संबंधी गतिविधियों की समीक्षा की।

कृषि विभाग कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में अपर कृषि निदेशक ने आत्मा परियोजना से जुड़े कार्मिकों एवं तकनीकी सहायकों के साथ विभागीय योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने खरीफ 2026 के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे प्रदर्शन कार्यक्रमों, किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था, बीज मिनीकिट की बुकिंग एवं वितरण, फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति तथा अन्य कृषि कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से पहुंचाया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो सकें।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने वन स्टॉप शॉप एग्री जंक्शन चरौली का भी दौरा किया। यहां किसानों को उपलब्ध कराई जा रही कृषि सेवाओं, कृषि यंत्रों, उन्नत बीज, उर्वरकों एवं तकनीकी सलाह की व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने किसानों को एक ही स्थान पर कृषि संबंधी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया।

इसके बाद डॉ. कनीज फातिमा ने प्राकृतिक खेती के अंतर्गत चयनित कृषि सखियों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। संवाद के दौरान उन्होंने प्राकृतिक खेती के महत्व, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने, कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करने तथा पर्यावरण संरक्षण में प्राकृतिक खेती की भूमिका पर चर्चा की। कृषि सखियों ने भी अपने अनुभव साझा किए और गांव स्तर पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।

इस अवसर पर उप कृषि निदेशक डॉ. राजेश कुमार, जिला कृषि अधिकारी डॉ. सतीश चंद्र पाठक, जिला कृषि रक्षा अधिकारी इन्द्रजीत यादव, भूमि संरक्षण अधिकारी द्वितीय डॉ. निधि राठौर, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. डी.बी. सिंह सहित कृषि विभाग के अधिकारी, आत्मा परियोजना के कार्मिक एवं तकनीकी सहायक मौजूद रहे।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने, वैज्ञानिक खेती को प्रोत्साहित करने, प्राकृतिक खेती के विस्तार तथा कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभाग पूरी गंभीरता से कार्य कर रहा है। खरीफ सीजन में किसानों को समय पर बीज, तकनीकी मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

...इससे जोड़ने पर बल दिया

भ्रमण के अंतिम चरण में अधिकारियों ने विकास खंड बिलग्राम स्थित बिलग्राम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (एफपीओ) का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने किसानों को संगठित कर कृषि उत्पादों के बेहतर विपणन, मूल्य संवर्धन, सामूहिक खरीद एवं बिक्री और किसानों की आय बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। अधिकारियों ने एफपीओ को और अधिक सशक्त बनाने तथा अधिक से अधिक किसानों को इससे जोड़ने पर बल दिया।

साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा रजडेरवा चौराहे पर जागरूकता अभियान, लोगों को दी गई सुरक्षा संबंधी अहम जानकारी

वेब वार्ता, कमर खान

गैसड़ी / बलरामपुर। थाना कोतवाली गैसड़ी की साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा आज रजडेरवा चौराहे पर मौजूद नागरिकों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचाव के महत्वपूर्ण उपाय बताए गए। टीम ने बताया कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन पर बैंक संबंधी जानकारी मांगे जाने पर उसे साझा न करें। रटर या हँ३२अस्रस्र के माध्यम से प्राप्त किसी भी संदिग्ध लिंक को न खोलें। बैंक से संबंधित कोई भी कार्य सीधे बैंक जाकर ही करें तथा अपने मोबाइल पर प्राप्त डळढ किसी से भी साझा न करें। इसके साथ ही अवैध या अवेरिफाइड ऐप डाउनलोड करने से बचने, फर्जी लॉटरी व इनाम संबंधी संदेशों पर ध्यान न देने और किसी भी प्रकार की योजना के नाम पर बैंक डिटेल साझा न करने की सलाह दी गई। यदि कोई व्यक्ति खुद को पुलिस, जज या कमिश्नर बताकर डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी देता है तो उससे न डरें और न ही किसी प्रकार की धनराशि ट्रांसफर करें।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि डिजिटल माध्यम से गिरफ्तारी नहीं की जाती है। ऐसे कॉल्स की सूचना तत्काल साइबर क्राइम पोर्टल पर देने की अपील की गई, ताकि अन्य लोग भी ठगी से बच सकें। साइबर हेल्पडेस्क टीम थाना कोतवाली गैसड़ी के थानाध्यक्ष दुर्विजय, साइबर प्रभारी वसी अहमद एवं टीम के सदस्य कांस्टेबल सुरजीत कुमार सिंह, कन्हैया लाल यादव तथा महिला कांस्टेबल सुषमा गौतम ने नागरिकों से अपील की कि किसी भी साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करें या पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। समय पर शिकायत करने से ठगी गई धनराशि को होल्ड कराकर वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

लंका पुलिस का नशा तस्करों पर शिकंजा

वाराणसी, वेब वार्ता। लंका पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए महिला समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से कुल 9 ग्राम हेरोइन बरामद की है। तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21/29 के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही आरोपियों के आपराधिक इतिहास और संभावित नेटवर्क की भी जांच की जा रही है।

बनारस की रहस्यमयी धरोहर

150 साल पुरानी देवकीनंदन हवेली, 10 बीघे में फैली 5 मंजिला आलीशान हवेली में एक दिन भी रह सके बनवाने वाले मालिक

वाराणसी, वेब वार्ता

काशी की पहचान केवल मंदिरों, घाटों और संकरी गलियों तक सीमित नहीं है। इस प्राचीन नगरी की हर गली, हर मोहल्ला और हर पुरानी इमारत अपने भीतर इतिहास का एक अनकहा अध्याय समेटे हुए है। इन्हीं विरासतों में शामिल है रामापुरा स्थित करीब 150 वर्ष पुरानी बाबू देवकीनंदन की हवेली, जिसकी भव्यता आज भी लोगों को आकर्षित करती है। पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी, विशाल बरामदे और शानदार स्थापत्य कला इस हवेली को बनारस की ऐतिहासिक धरोहरों में अलग पहचान देते हैं। लेकिन इस हवेली की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे बनवाने वाले बाबू देवकीनंदन स्वयं इसमें एक दिन भी नहीं रह सके।

वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु राज पांडेय के अनुसार, बाबू देवकीनंदन मूल रूप से प्रयागराज के निवासी थे। ब्रिटिश शासनकाल में उनका अंग्रेज अधिकारियों से अच्छा संबंध था। इसी कारण अंग्रेज सरकार ने उन्हें वाराणसी के रामापुरा क्षेत्र की प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके बाद उन्होंने प्रयागराज छोड़कर काशी में अपना स्थायी निवास बनाने का निर्णय लिया।

रामापुरा क्षेत्र में लगभग 10 बीघे भूमि पर बाबू देवकीनंदन ने उस समय की आधुनिक सोच और भारतीय स्थापत्य शैली का अद्भुत संगम प्रस्तुत करने वाली एक विशाल हवेली का निर्माण कराया। पत्थरों से निर्मित इस भवन में बारीक नक्काशी, बड़े-बड़े दरवाजे, ऊंची छतें और प्राकृतिक रोशनी व हवा के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। हवेली का प्रत्येक हिस्सा उस दौर की समृद्ध वास्तुकला का उदाहरण माना जाता है। इस हवेली से जुड़ी सबसे चर्चित कहानी उस समय की है, जब अंग्रेज सरकार ने विशेष आदेश पर इंग्लैंड से केवल तीन आधुनिक लिफ्ट भारत मंगवाई थीं। बाबू देवकीनंदन चाहते थे कि उन तीन लिफ्टों में से एक उनकी हवेली में स्थापित हो, ताकि उनकी कोठी उस दौर की सबसे आधुनिक इमारतों में शामिल हो सके।

मिशन सेफ फ्यूचर अभियान के तहत हरदोई में स्कूली वाहनों पर कार्रवाई, दो अनफिट वाहनों का चालान

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। प्रदेश सरकार के निर्देश पर चलाए जा रहे 'मिशन सेफ फ्यूचर' अभियान के तहत हरदोई में परिवहन विभाग ने स्कूली वाहनों की सघन जांच की। अभियान के दौरान 15 स्कूली वाहनों की जांच की गई, जिसमें सुरक्षा मानकों पर खरे न उतरने वाले दो अनफिट स्कूली वाहनों का चालान किया गया। वहीं, स्कूल वाहन के रूप में संचालित एक निजी पीले रंग के वाहन को नियमों के उल्लंघन पर निरुद्ध (सीज) कर दिया गया।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि 1 से 15 जुलाई तक चल रहे इस विशेष अभियान का उद्देश्य स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है। जांच के दौरान वाहनों की फिटनेस, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जा रही है। साथ ही विभागीय टीमें विभिन्न विद्यालयों में पहुंचकर वाहनों का भौतिक निरीक्षण कर रही हैं और वाहन स्वामियों को समय पर दस्तावेजों का नवीनीकरण कराने के लिए जागरूक भी कर रही हैं।

परिवहन विभाग ने सभी स्कूल संचालकों और वाहन स्वामियों से अपील की है कि जिन वाहनों की फिटनेस, परमिट, बीमा अथवा प्रदूषण प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त हो चुकी है, उनका तत्काल नवीनीकरण करा लें। अन्यथा मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

विभाग के अनुसार 8 से 15 जुलाई तक पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से विशेष प्रवर्तन अभियान चलाएंगे। इस दौरान बिना फिटनेस, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र या अन्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर स्कूली बच्चों का परिवहन करने वाले वाहनों के विरुद्ध चालान, सीज सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आम के पेड़ के नीचे अचेत मिली हाईस्कूल की छात्रा, गले पर चोट के निशान; ट्रॉमा सेंटर रेफर

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। अतरौली थाना क्षेत्र में आस्तिकन से ताजपुर जाने वाली सड़क के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे हाईस्कूल की छात्रा अचेत अवस्था में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

छात्रा गांव से लगभग 500 मीटर दूर पड़ी मिली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे तत्काल सीएचसी भरावन पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया।

चिकित्सकों के अनुसार छात्रा के गले पर चोट के निशान पाए गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक सुबोध गौतम तथा फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए।

पुलिस के अनुसार घटनास्थल के पास एक आधार कार्ड, शराब की बोतल तथा अन्य सामान बरामद हुआ है। इन साक्ष्यों के आधार पर पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।

छात्रा के पिता की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले का शीघ्र खुलासा किया जाएगा। फिलहाल घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच जारी है।

हरदोईः डीएम ने UPTET-2026 परीक्षा केंद्र का किया निरीक्षण

निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण परीक्षा कराने के दिए निर्देश

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अनुनय झा ने शनिवार को परीक्षा के तीसरे दिन प्रथम पाली के दौरान श्री वेणी माधव इंटर कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने आयोग एवं शासन द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के लिए पेयजल, स्वच्छ शौचालय तथा अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहनी चाहिए।

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि प्रत्येक परीक्षार्थी की निर्धारित मानकों के अनुरूप जांच कराई जाए तथा परीक्षा को पूरी तरह शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जाए। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सतत निगरानी बनाए रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन के मानकों के अनुरूप सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही संबंधित अधिकारियों को भ्रमणशील रहकर परीक्षा व्यवस्थाओं का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में 'डीआईसी' पर सीएमई का हुआ आयोजन

वेब वार्ता, कानपुर। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग द्वारा 'डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलोपैथी' (डीआईसी) विषय पर एक दिवसीय सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) सम्मेलन का आयोजन किया गया। चूंकि डीआईसी गर्भवती महिलाओं में मातृ मृत्यु के सबसे प्रमुख और गंभीर कारणों में से एक है, इसलिए इस विषय पर चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत और व्यावहारिक जानकारी साझा की गई।

कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉ. नीना गुप्ता ने डीआईसी के अंतर्निहित कारणों, शुरूआती लक्षणों की पहचान, आधुनिक उपचार पद्धतियों और इसके प्रभावी प्रबंधन पर व्यावहारिक व्याख्यान दिया। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि सही समय पर सटीक उपचार शुरू करके मातृ मृत्यु दर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की प्रोफेसर व कार्यवाहक विभागाध्यक्ष डॉ. सीमा द्विवेदी ने की। उन्होंने गंभीर परिस्थितियों में 'टीम प्रबंधन' और गर्भवती महिलाओं को बिना देरी किए उचित चिकित्सा उपलब्ध कराने के महत्व को रेखांकित किया। कार्यक्रम का कुशल संचालन डॉ. रश्मि यादव एवं डॉ. दिव्या गुप्ता द्वारा किया गया। डीआईसी के जटिल उपचार को देखते हुए इस सम्मेलन में बहुविषयक दृष्टिकोण पर चर्चा की गई। इस बीमारी से निपटने के लिए सभी वरिष्ठ चिकित्सकों ने अपने महत्वपूर्ण नैदानिक अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. रेनू गुप्ता एवं सीएमएस डॉ. अनीता गौतम समेत प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के सभी संकाय सदस्यो और स्नातकोत्तर (पीजी) विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सम्मेलन के अंतिम चरण में एक इंटरैक्टिव प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने विशेषज्ञों से अपनी शंकाओं का समाधान किया। यह संगोष्ठी सभी चिकित्सकों और भावी डॉक्टरों के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक और उपयोगी सिद्ध हुई। इस अवसर पर मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ. एस. के. गौतम, पैथोलॉजी विभाग की प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉ. लुबना खान और एनेस्थीसिया विभाग की प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉ. अपूर्वा अग्रवाल उपस्थित रहे।

नगर निगम ने कैंट स्टेशन के सामने चलाया अभियान, अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा

वाराणसी, 04 जुलाई (वेब वार्ता)। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने और यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के उद्देश्य से नगर निगम ने शुक्रवार को कैंट रेलवे स्टेशन के सामने और आसपास के इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान सड़क और फुटपाथ पर अवैध रूप से रखे गए सामान तथा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं कई दुकानदारों पर जुमार्ना भी लगाया। नगर निगम की कार्रवाई से क्षेत्र के दुकानदारों और अतिक्रमणकारियों में हड़कंप की स्थिति रही। अभियान के दौरान नगर निगम की अतिक्रमण प्रवर्तन टीम ने सार्वजनिक मार्गों पर कब्जा कर व्यापार करने वाले कई दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मौके पर ही आर्थिक दंड भी लगाया। अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करने वालों से हजारों रुपये का जुमार्ना वसूला और उन्हें भविष्य में दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की सख्त चेतावनी दी।

महत्वपूर्ण ख़बर

जिसने उड़ा दी सीबीएसई की नींद, उस हैकर की मंत्री ने की तारीफ

■ कोलकाता। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने बंगाल के युवा एथिकल हैकर निसर्ग अधिकारी की जमकर सराहना की है। निसर्ग वही प्रतिभाशाली छात्र हैं, जिसने हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की वेबसाइट में ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम की सुरक्षा खामियों को उजागर कर दिया था। कोलकाता में इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एजुकेशन फॉर विकसित भारत कॉन्क्लेव में मजूमदार ने निसर्ग की इस उपलब्धि को बंगाल का टैलेंट बताया और कहा कि यह एक 10वीं पास छात्र की असाधारण विशेषज्ञता का प्रमाण है। मंत्री ने बताया कि सरकार ने निसर्ग की प्रतिभा को सही दिशा दी और उसे आईआईटी-कानपुर के साइबर सिक्योरिटी सेंटर से जोड़ा, जहाँ अब वह थ्रेट इंटेलिजेंस इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं। मजूमदार ने कहा कि निसर्ग चाहते तो किसी विरोध-प्रदर्शन का हिस्सा बन सकते थे, लेकिन सरकार ने उन्हें सीखने और देश के विकास में योगदान देने का एक बेहतर मंच प्रदान किया। निसर्ग अधिकारी तब चर्चा में आए थे जब सीबीएसई ने 12वीं के नतीजे घोषित किए थे और नए ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम का उपयोग किया था।

सिंधु जल संधि

जल संकट में ड्रैगन को घसीट रहा पाकिस्तान

इस्लामाबाद। पाकिस्तान दशकों से सिंधु जल समझौते से लाभ उठा रहा था, अपनी प्यास बुझा रहा था, लेकिन सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने की नीतियों ने भारत को सिंधु जल संधि पर अपने रुख की समीक्षा करने पर मजबूर कर दिया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सीमा पार आतंकवाद जारी रहेगा, तब तक सिंधु जल संधि पर पहले जैसी व्यवस्था नहीं चल सकती। इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान चीन की गोद में बैठकर कुदरत की सौगातों का पाठ पढ़ा रहा है। पाकिस्तान का तर्क है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां सिर्फ भारत और पाकिस्तान की नहीं हैं, बल्कि चीन भी इनका एक बड़ा हितधारक है, और इस मुद्दे पर उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है।

पाकिस्तान ने अचानक चीन को जल सिंधू विवाद में क्यों घसीटा, यह समझना जरूरी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने हाल ही में कहा कि हिमालय से निकलने वाली नदियां कुदरत की देन हैं और ये सिंधु से लेकर मेकांग तक कई देशों को पानी देती हैं। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि चीन से भी कई बड़ी नदियां निकलती हैं, इसलिए पानी का मुद्दा पूरी मानवता से जुड़ा है और चीन की भूमिका भी इसमें अहम है। पाकिस्तान यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि यह सिर्फ भारत-पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र का एक साझा मुद्दा है, जिसमें चीन एक महत्वपूर्ण पक्षकार है। ताहिर अंद्राबी ने अपने बयान में जोर दिया कि चीन का रुख पानी से जुड़े बड़े मुद्दों पर हमेशा सकारात्मक रहेगा, क्योंकि वह न सिर्फ दक्षिण एशिया में बहने वाली नदियों के मामले में, बल्कि हिमालय से चीन और सुदूर पूर्व की ओर बहने वाली विशाल नदी प्रणालियों के मामले में भी एक अहम पक्षकार है। अब सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान ने चीन का नाम क्यों लिया। इसका सीधा जवाब है - भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाना। सिंधु जल को लेकर भारत के सख्त रुख के बाद पाकिस्तान छटपटा रहा है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि पहले आतंकवाद रोको, तभी द्विपक्षीय संबंध सामान्य हो सकते हैं।

पाकिस्तान को उम्मीद है कि चीन, जो उसका एक सदाबहार दोस्त और सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार रहा है, उसके समर्थन में आवाज उठा सकता है। दोनों देशों के बीच चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) जैसी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। हालांकि, बीते कुछ समय से भारत-चीन के रिश्तों में भी सुधार आया है, और अमेरिका की टैरिफ नीति के चलते दोनों देशों में नजदीकियां बढ़ी हैं। ऐसे में पाकिस्तान को चीन से खुलकर समर्थन मिलने और भारत का खुलकर विरोध करने की संभावना बहुत कम दिखती है।इसके अलावा, भारत-पाकिस्तान के इस सिंधु जल मसले पर चीन के दखल न देने की एक और बड़ी वजह है। सिंधु जल विवाद का आधार सिंधु जल संधि है, जो केवल भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। इसमें चीन किसी भी रूप में पक्षकार नहीं है। इसलिए, चीन चाहकर भी दो देशों के इस द्विपक्षीय मसले में मौजूदा हालात में न तो बोलेगा और न ही दखल देगा।

भारत करेगा 5 हजार करोड़ की डील, राफेल को मिलेंगी 600 हैमर मिसाइलें

दुश्मन होगा पस्त, भारतीय वायुसेना और नौसेना की ताकत में होगा इजाफा

नई दिल्ली। भारत जल्द ही 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की एक बड़ी रक्षा डील करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य चीन और पाकिस्तान की बढ़ती चुनौतियों का सामना करना है। यह डील भारतीय सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करेगी और देश की रक्षा क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि लाएगी। नए सीडीएस जनरल राजा सुब्रमणि, थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ और नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन की मौजूदगी में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की एक उच्चस्तरीय बैठक में कई अहम रक्षा परियोजनाओं को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है।

इस महाडील का मुख्य आकर्षण 600 हैमर एयर-टू-ग्राउंड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइलें होंगी। इन मिसाइलों को भारतीय वायुसेना के राफेल और स्वदेशी एलसीए तेजस जैसे फाइटर जेट्स में लगाया जाएगा, जिससे भारत की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। करीब 2,400 करोड़ रुपए की यह हैमर मिसाइल डील भारतीय वायुसेना और नौसेना की ताकत में एक बड़ा इजाफा है। फ्रांस की कंपनी सफरान द्वारा विकसित इन मिसाइलों का निर्माण अब मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (भेल) द्वारा किया जाएगा। भारतीय नौसेना भी अपने आगामी राफेल मरीन फाइटर जेट्स को इन घातक मिसाइलों से लैस करेगी, जो सामरिक रूप से बेहद अहम है। इस बैठक में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित पूरी तरह स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम को भी मंजूरी मिल सकती है। यह मिसाइल दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को अत्यधिक सटीकता से निशाना बनाने में सक्षम है। इस परियोजना के तहत भारतीय सेना को 100 उन्नत लॉन्चर, 2,300 मिसाइलें और सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए 5 आधुनिक सिमुलेटर मिलेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 2,600 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। इन मिसाइलों का निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जिसमें उत्पादन में तेजी लाने के लिए निजी कंपनियों को भी शामिल करने की योजना है। यह कदम देश की रक्षा विनिर्माण क्षमता को मजबूत करेगा।

इसके साथ ही, भारतीय सेना को जल्द ही रूसी मूल की वेरबा वी-शॉराड्स मिसाइल प्रणाली भी मिलने की उम्मीद है। यह प्रणाली दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को कुछ ही सेकंड में बेअसर कर सकती है। इस मिसाइल के शामिल होने से वास्तविक नियंत्रण रेखा और नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना की हवाई रक्षा क्षमता में कई गुना बढ़ोतरी होगी। इन सभी डील्स का मुख्य लक्ष्य भारतीय सेना को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करना और चीन-पाकिस्तान जैसे देशों की नापाक हरकत का जवाब देने के लिए भारत की सैन्य ताकत को और ज्यादा मजबूत बनाना है।

काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट पर कार्बाइन से चली गोली, तीन लोग घायल

वाराणसी।श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर चार पर शनिवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही की कार्बाइन से अचानक गोली चल गई। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गोली सड़क पर जाकर लगी और उससे छिटकी गिट्टियों ने पास में मौजूद दो दुकानदारों और एक अन्य व्यक्ति को घायल कर दिया। इस घटना में तीन लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें तत्काल कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल ले जाया गया। राहत की बात यह है कि सभी घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और उन्हें हल्की चोटें आई हैं। जिस सिपाही की कार्बाइन से गोली चली, वह मंदिर की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात था।

घटना के बाद, मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने तुरंत घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के अनुसार, घायल हुए लोगों की पहचान निक्की गुप्ता, रामबाबू और विकास यादव के रूप में हुई है, जिनके हाथ और पैर में हल्की चोटें आई हैं और उनकी हालत स्थिर है। गोली चलने की तेज आवाज सुनते ही मंदिर परिसर और आसपास मौजूद लोगों में कुछ देर के लिए दहशत

फैल गई। हालांकि, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया ताकि किसी तरह की भगदड़ न मचे। जिस पीएसी सिपाही की कार्बाइन से यह दुर्घटना हुई, उसे घटना के तुरंत बाद चौक थाने ले जाया गया है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है कि कार्बाइन किस परिस्थिति में गिरी और गोली आखिर कैसे चल गई।

शुरूआती जानकारी के अनुसार, घायल हुए लोग मंदिर के पास फूल-माला का कारोबार करते हैं। डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि सभी घायलों की हालत सामान्य है और वे खतरे से बाहर हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। काशी विश्वनाथ मंदिर एक अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जहाँ रोजाना हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था हमेशा से ही कड़ी रहती है ताकि ऐसी किसी भी अप्रत्याशित घटना से बचा जा सके। इस तरह की घटना सुरक्षा प्रोटोकॉल और हथियारों के रखरखाव पर गंभीर सवाल उठाती है। पुलिस जांच के बाद ही कार्बाइन गिरने और गोली चलने के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सुरक्षाकर्मी अपने हथियारों को संभालने में पूरी सावधानी बरतें और आपातकालीन प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें।

बसों में भीषण आग के हादसों में जा रही यात्रियों की जान

नई दिल्ली। राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे हुए भीषण बस हादसे ने एक बार फिर लंबी दूरी की यात्री बसों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हरिद्वार से इंदौर जा रही एक स्लीपर बस ट्रक से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गई। हादसे के समय बस में करीब 37 यात्री सवार थे। दुर्घटना में आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 यात्री घायल हुए हैं। यह घटना देर रात हुई। टक्कर के बाद बस में आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरी बस जलकर खाक हो गई। घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले कुछ महीनों में देश के कई राज्यों में बसों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं। अक्टूबर 2025 में राजस्थान के जैसलमेर में विद्युत प्रणाली में खराबी के कारण बस में आग लगने से 22 लोगों की मौत हो गई थी। इसी महीने आंध्र प्रदेश के कुरनूल में बाइक से टक्कर के बाद बस में भीषण आग लग गई, जिसमें कई यात्रियों की जान चली गई। मार्च 2026 में आंध्र प्रदेश के माकार्पुरम में बस और टिप्पर की टक्कर के बाद लगी आग में भी कई लोगों की मौत हो गई थी।

क्या मोबाइल ऐप से बीच सड़क में बंद हो सकता है ई-रिक्शा?

नई दिल्ली। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हुए हैं। जिनमें दावा किया जा रहा है कि सिर्फ एक मोबाइल ऐप की मदद से चलते हुए ई-रिक्शा को बीच सड़क पर रोका जा सकता है। इन वीडियो के बाद लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि क्या इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक कारें भी इसी तरह हैक होकर बंद की जा सकती हैं? इसका जवाब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस) और उसमें मौजूद सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा है। दरअसल, बीएटी-बीएमएस ऐप को लिथियम-आयन बैटरियों की निगरानी और रखरखाव के लिए विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य बैटरी का चार्ज लेवल, तापमान, सेल की स्थिति और अन्य तकनीकी जानकारियां उपलब्ध कराना है। लेकिन कुछ शरारती तत्व उन ई-रिक्शों को निशाना बना रहे हैं, जिनकी बैटरियों में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है।

कमजोर बीएमएस सुरक्षा बन सकती है खतरा

विशेषज्ञों के मुताबिक, कई सस्ते ई-रिक्शों में ब्लूटूथ-सक्षम बीएमएस लगा होता है। यदि इस सिस्टम पर पासवर्ड या पिन सुरक्षा नहीं है, तो करीब 10 से 15 मीटर की दूरी से कोई भी व्यक्ति मोबाइल ऐप के जरिए उससे कनेक्ट हो सकता है। कनेक्शन बनने के बाद यदि ऐप में मौजूद पावर या डिस्चार्ज कंट्रोल को बंद कर दिया जाए, तो बैटरी से मोटर तक बिजली की आपूर्ति रुक जाती है और ई-रिक्शा चलना बंद हो सकता है।

हर ई-रिक्शा खतरे की जद में नहीं

हालांकि, यह खतरा सभी ई-रिक्शों पर लागू नहीं होता। जिन बैटरियों में ब्लूटूथ पासवर्ड, पिन या अन्य सुरक्षा प्रणाली से सुरक्षित है, उनमें अनधिकृत व्यक्ति कनेक्ट नहीं हो सकता। वहीं, पारंपरिक लेड-एसिड बैटरी वाले ई-रिक्शों में ब्लूटूथ आधारित बीएमएस नहीं होता, इसलिए उनमें इस तरह की समस्या नहीं आती।

इलेक्ट्रिक स्कूटर और कारें सुरक्षित?

इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक कारों को लेकर भी लोगों में भ्रम है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि प्रतिष्ठित कंपनियों के अधिकांश इलेक्ट्रिक स्कूटर और लगभग सभी इलेक्ट्रिक कारों में अत्याधुनिक बीएमएस, डेटा एन्क्रिप्शन, सुरक्षित संचार प्रणाली, पासवर्ड सुरक्षा और क्लाउड आधारित प्रमाणीकरण जैसी कई सुरक्षा परतें होती हैं। ऐसे वाहनों को केवल ब्लूटूथ के जरिए किसी सामान्य मोबाइल ऐप से बंद करना लगभग असंभव है।

ई-रिक्शा मालिकों के लिए सलाह

विशेषज्ञ ई-रिक्शा मालिकों और संचालकों को सलाह देते हैं कि वे अपनी बैटरी के बीएमएस की सुरक्षा जरूर जांचें। यदि ब्लूटूथ बिना पासवर्ड के खुला है, तो उसे तुरंत सुरक्षित कराएं या निमार्ता से सुरक्षा अपडेट लें। विशेषज्ञों का कहना है कि बीएटी- बीएमएस जैसे ऐप अपने आप में खतरा नहीं हैं, बल्कि कमजोर सुरक्षा वाली बैटरियों में उनका गलत इस्तेमाल चिंता का विषय है। इसलिए बैटरी निमार्ताओं और वाहन मालिकों दोनों को साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि तकनीक लोगों की सुविधा बढ़ाए, न कि सुरक्षा के लिए खतरा बने।

ऐसे तो चिकन नेक के पास दस्तक देंगे चीनी सैनिक ?

नई दिल्ली। भारत ने बांग्लादेश के साथ चीन की बढ़ती साझेदारी, खासकर तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना और प्रस्तावित चीन-बांग्लादेश-म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर (सीबीएमईसी) को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर अपनी सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि नई दिल्ली अपने पड़ोस में होने वाले सभी घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखे हुए है और आवश्यकता पड़ने पर उचित कदम उठाएगी। भारत ने पहले ही बांग्लादेश को तीस्ता परियोजना पर अपने विचारों से अवगत करा दिया है, और उसने स्पष्ट किया है कि भारत की विकास सहायता दोनों देशों के बीच आपसी सहमति वाले रोडमैप पर आधारित है, जिसकी नियमित समीक्षा होती है।

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने पिछले महीने चीन का दौरा किया था, जहां उन्होंने तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट पर सहयोग के लिए सहमति जताई। चीन ने सीबीएमईसी को भी आगे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिससे बीजिंग को बंगाल की खाड़ी तक सीधी पहुंच मिल सकेगी। इस दौरान, पीएम रहमान ने चीन के जल संसाधन मंत्री ली गुओयिंग से मुलाकात की और तीस्ता परियोजना सहित नदी प्रबंधन के लिए तकनीकी

सहायता मांगी। चीन ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है, और चीनी विशेषज्ञ पहले ही इस परियोजना की व्यवहार्यता अध्ययन कर चुके हैं। ढाका में चीनी राजदूत याओ वेन ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उनका देश सीबीएमईसी और तीस्ता परियोजना पर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के लिए ये घटनाक्रम रणनीतिक रूप से संवेदनशील हैं। अगर सीबीएमईसी परियोजना पूरी होती है, तो चीन को बंगाल की खाड़ी तक सीधी पहुंच मिल जाएगी, जिससे इस महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र में उसकी उपस्थिति बढ़ जाएगी। इसके अलावा, तीस्ता परियोजना में चीनी कर्मियों की भागीदारी भारत के संवेदनशील चिकन नेक कॉरिडोर के करीब उनकी मौजूदगी को बढ़ा सकती है। यह संकरा गलियारा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है और इसकी सुरक्षा भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत ने जून 2024 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान बांग्लादेश के भीतर तीस्ता नदी के संरक्षण का जिम्मा लेने में अपनी रुचि व्यक्त की थी। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि तीस्ता के संरक्षण और प्रबंधन पर बातचीत के लिए एक भारतीय तकनीकी टीम ढाका का दौरा करेगी। भारत और बांग्लादेश के बीच 54 सीमा पार नदियां हैं, लेकिन तीस्ता एकमात्र ऐसी नदी है जिसके लिए दोनों देशों के बीच कोई जल-बंटवारा समझौता नहीं है, जो इस मुद्दे को और भी जटिल बनाता है। भारत इस पूरे घटनाक्रम को अपने समग्र दृष्टिकोण में ध्यान में रखेगा।

वॉट्सऐप ने किया यूजरनेम फीचर का ऐलान, बढ़ेगी यूजर्स की निजता

नई दिल्ली। वॉट्सऐप कंपनी ने आधिकारिक तौर पर ह्ययूजरनेमह्ल फीचर का ऐलान कर दिया है, जिसकी मदद से यूजर्स अब बिना अपना मोबाइल नंबर शेयर किए भी दूसरे लोगों से बातचीत कर सकेंगे। वॉट्सऐप का यह एक क्रांतिकारी बदलाव है जो यूजर्स की निजता को कई गुना बढ़ा देगा। फिलहाल, वॉट्सऐप ने यूजरनेम रिजर्व करने की सुविधा शुरू कर दी है, और यह फीचर आने वाले महीनों में धीरे-धीरे सभी देशों में रोलआउट किया जाएगा। अभी तक वॉट्सऐप पर किसी नए व्यक्ति से बात करने के लिए उसका फोन नंबर शेयर करना और उसे अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव करना अनिवार्य होता था। लेकिन नए यूजरनेम फीचर के लागू होने के बाद, यूजर्स अपना एक यूनिक यूजरनेम चुन सकेंगे और दूसरे लोग केवल उसी यूजरनेम के जरिए उनसे संपर्क स्थापित कर पाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो किसी नए समूह, कम्युनिटी या किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ना चाहते हैं जिसे वे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, लेकिन अपना पर्सनल मोबाइल नंबर साझा करने में सहज महसूस नहीं करते। यह फीचर ऑनलाइन प्राइवेसी को लेकर बढ़ती चिंताओं का एक सीधा समाधान प्रदान करता है।

वॉट्सऐप ने स्पष्ट किया है कि इस फीचर में कोई पब्लिक डायरेक्टरी या सर्च लिस्ट नहीं होगी। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति आपका यूजरनेम आसानी से खोज नहीं पाएगा, जिससे आपकी पहचान और भी सुरक्षित रहेगी। किसी को आपसे पहली बार संपर्क करने के लिए आपका सही और सटीक यूजरनेम पता होना जरूरी होगा। यह अनचाहे संदेशों और स्पैम से बचाव में भी मदद करेगा। इसके अतिरिक्त, कंपनी एक ह्ययूजरनेम कीह्ल फीचर भी दे रही है। इस फीचर को ऑन करने पर, किसी नए व्यक्ति को आपको मैसेज भेजने के लिए इस अतिरिक्त सिक्योरिटी की की भी जरूरत होगी। यह सुरक्षा की एक और परत जोड़ता है, जिससे अनजान लोगों द्वारा भेजे जाने वाले मैसेज और स्पैम से बचाव और भी प्रभावी हो जाएगा।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर भड़के महंत, बोले- दोषियों को सीधे फांसी दे दो

अयोध्या। नवनिर्मित भव्य राम मंदिर में रामलला के चरणों में आने वाले चढ़ावे में कथित हेराफेरी के मामले ने अब एक गंभीर मोड़ ले लिया है। इस मामले पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और प्रतिष्ठित महंत दिनेंद्र दास महाराज ने बेहद आक्रामक रुख अपनाया है। उन्होंने दोषियों के लिए सबसे कड़ी सजा की मांग करते हुए दोटूक शब्दों में कहा कि भगवान के घर में इस तरह का अपराध करने वालों को सीधे फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। यह बयान इस बात को दर्शाता है कि धार्मिक संस्थाओं में वित्तीय अनियमितता को कितना गंभीर अपराध माना जाता है, खासकर एक ऐसे मंदिर में जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। इस बीच, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने इस मामले में अपनी जांच तेज कर दी है। एसआईटी ने मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि वित्तीय हेरफेर के पूरे नेटवर्क का पदार्फाश किया जा सके और गबन किए गए धन की रिकवरी की जा सके।

ओटीटी की बढ़त से डीटीएच और केबल पर छाया संकट

ट्राई रिपोर्ट के मुताबिक पेड डीटीएच ग्राहक घटकर 4.90 करोड़ हुए

नई दिल्ली। देश में मनोरंजन के तौर-तरीकों में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। स्मार्ट टीवी, हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड और ओटीटी प्लेटफॉर्म की बढ़ती लोकप्रियता के चलते पारंपरिक डीटीएच और केबल सेवाओं का ग्राहक आधार लगातार घट रहा है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की ताजा परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2026 की तिमाही के अंत तक देश में सक्रिय पेड डीटीएच ग्राहकों की संख्या घटकर 4.90 करोड़ (49.05 मिलियन) रह गई, जबकि दिसंबर 2025 में यह आंकड़ा 5.10 करोड़ (50.99 मिलियन) था। यानी मात्र 90 दिनों में करीब 19.4 लाख ग्राहकों ने डीटीएच सेवा छोड़ दी।

उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट केवल डीटीएच तक सीमित नहीं है। केबल टीवी नेटवर्क भी तेजी से सिमट रहा है। मध्य प्रदेश में जहां कुछ वर्ष पहले 18 से 20 लाख घरों में केबल कनेक्शन थे, वहीं अब इसकी पहुंच काफी घट चुकी है। अनुमान है कि मनोरंजन बाजार में अब लगभग 60 प्रतिशत हिस्सेदारी ओटीटी प्लेटफॉर्म की हो चुकी है, जबकि

केबल और डीटीएच का हिस्सा करीब 20-20 प्रतिशत रह गया है।

विशेषज्ञों का मानना है, कि उपभोक्ताओं के लिए ब्रॉडबैंड आधारित बंडल प्लान अधिक किफायती साबित हो रहे हैं। एक ही पैकेज में हाई-स्पीड इंटरनेट, लाइव टीवी चैनल और कई ओटीटी प्लेटफॉर्म की सदस्यता उपलब्ध होने से लोग पारंपरिक टीवी सेवाओं की बजाय डिजिटल विकल्पों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

इस संबंध में केबल ऑपरेटर बताते हैं कि पिछले पांच वर्षों में शहर में ही केबल कनेक्शनों की संख्या लाखों में घटी है और अब हजारों में रह गई है। इसकी मुख्य वजह जहां कनेक्शन महंगा होना बताया जाता है वहीं अब उपभोक्ता तय समय पर प्रसारित होने वाले चैनलों की बजाय अपनी सुविधानुसार पसंदीदा कंटेंट देखना चाह रहे हैं।

दूरसंचार विशेषज्ञों का कहना है कि सस्ते इंटरनेट, 5जी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (एफडब्ल्यूए) और स्मार्ट टीवी के प्रसार ने इस बदलाव को और गति दी है। मार्च 2026 तक देश में 5जी एफडब्ल्यूए कनेक्शनों की संख्या 1.25 करोड़ के पार पहुंच चुकी है और अप्रैल में इसमें और वृद्धि दर्ज की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में मनोरंजन उद्योग का केंद्र पारंपरिक प्रसारण सेवाओं से हटकर इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म की ओर और तेजी से स्थानांतरित होगा।

नागरिक सुविधाओं के काम में न हो लापरवाही : श्रीमती शंगीता आर.

नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव ने की रायपुर नगर निगम के कार्यों की समीक्षा

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव श्रीमती शंगीता आर. ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ रायपुर नगर निगम के अधिकारियों की बैठक लेकर राजधानी रायपुर में विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने रायपुर नगर निगम मुख्यालय में आयोजित बैठक में तकनीकी कारणों से लंबित अप्रारंभ कार्यों की बाधाएं दूर कर उन्हें तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

उन्होंने सभी जोन कमिश्नरों को हर 15 दिनों में कार्यस्थलों का निरीक्षण कर प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक श्री आर. एक्का और रायपुर नगर निगम के आयुक्त संबित मिश्रा भी बैठक में मौजूद थे।

सचिव श्रीमती शंगीता आर. ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि राजधानी में नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट तथा अन्य बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए सभी जोन कमिश्नरों, स्वच्छ भारत मिशन के वार्ड प्रभारियों और नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारियों का गंभीरता एवं जवाबदेही के साथ निर्वहन करने को कहा। नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव ने शहर के जलभराव वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर व्यापक सफाई अभियान चलाने तथा जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी नियमित एवं प्लेसमेंट अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्धारित समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलने से कार्यक्षमता और सेवा वितरण दोनों बेहतर होते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए अभियान तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के आवासों के निर्माण में तेजी लाने को कहा। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की समीक्षा के दौरान रायपुर की स्वच्छता रैंकिंग को सुधारने पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने को कहा।

सचिव श्रीमती शंगीता आर. ने राजधानी की गरिमा के अनुरूप स्वच्छता व्यवस्था विकसित करने, शत-प्रतिशत डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण सुनिश्चित करने तथा कचरा परिवहन की व्यवस्था की नियमित निगरानी व समीक्षा करने को कहा। उन्होंने नालंदा परिसर की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। राज्य शहरी विकास अभिकरण (स्ष्ठ) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शशांक पाण्डेय, नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक श्री पुलक भट्टाचार्य, मुख्य अभियंता श्री राजेश शर्मा और रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त संचालक श्री एस.के. सुन्दरानी सहित नगर निगम के सभी अपर आयुक्त, उपायुक्त, जोन कमिश्नर, अभियंता, सभी विभागों के प्रभारी अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन के वार्ड प्रभारी, जोन स्वास्थ्य अधिकारी तथा जोन सहायक राजस्व अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

ताजा खबर

संक्षिप्त

श्रमिक कार्ड में त्रुटि होने पर तत्काल सुधार कराएं, मात्र 20 रुपये में उपलब्ध है सुविधा

रायपुर. छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों को अपने श्रमिक कार्ड में दर्ज जानकारी का समय-समय पर सत्यापन कर आवश्यक सुधार कराने की सलाह दी गई है। यदि श्रमिक कार्ड में नाम (हिंदी एवं अंग्रेजी), जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल नंबर अथवा पूर्ण पते से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि है, तो उसे तत्काल संशोधित कराना चाहिए, ताकि भविष्य में शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अधिकारियों ने बताया कि श्रमिक कार्ड में संशोधन का कार्य के लिए मात्र 20 रुपये का निर्धारित सेवा शुल्क लिया जाएगा। इसके लिए श्रमिकों को आधार कार्ड की मूल प्रति तथा सहमति पत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। सभी दस्तावेज स्पष्ट एवं पठनीय होना आवश्यक है। श्रम विभाग ने पंजीकृत श्रमिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने श्रमिक कार्ड की जानकारी अपडेट कराएं।

गीत-संगीत और नुक्कड़-नाटक से नशा छोड़ने का मैसेज

रायपुर. राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) दुर्गा महाविद्यालय, माय भारत और समाज कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में पुरैना हाई स्कूल और समता कॉलोनी स्थित सियान गुड़ी में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान गीत, संगीत, स्लोगन और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से छात्रों एवं आम लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया।कार्यक्रम अधिकारी सुनीता चंसोरिया ने सभी उपस्थित लोगों को नशा न करने की शपथ दिलाई। एनएसएस के स्वयंसेवकों ने स्लोगन और नुक्कड़ नाटक पेश कर नशे के दुष्प्रभावों से छात्रों को बताए। वहीं, समाज कल्याण विभाग के संतोष चंद्राकर, रमेश ठाकुर और परमात्मा वस्त्राकार ने प्रेरणादायक गीतों के माध्यम से लोगों को नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए जागरूक किया।

रायपुर रेल मंडल के 13 स्टेशन होंगे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से लैस, 226 करोड़ मंजूर

रायपुर। रेलवे बोर्ड ने दक्षिण पूर्व मध्य रेल (एसईसीआर) के रायपुर डिवीजन के दुर्ग-तारोकी खंड के 13 स्टेशनों पर 226 करोड़ रुपये की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (ईआई) प्रणाली की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में 13 स्टेशनों पर मौजूदा पैनल इंटरलॉकिंग (पीआई) प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (ईआई) प्रणाली से बदला जाएगा।इससे सुरक्षित, अधिक विश्वसनीय और प्रौद्योगिकी-आधारित ट्रेन परिचालन संभव हो सकेगा। स्वीकृत परियोजना में रायपुर डिवीजन के दुर्ग-तारोकी खंड के मारौडा (एमएक्सए), रिसमा (आरएसए), गुंडार्देही (जीडीजेड), लाटाबोर (एलबीओ), बलोद (बीएक्सए), कुसुमकासा (केवाईएस), दल्ली राजहरा (डीआरजेड), गुडम (जीयूडीएम), भानुप्रतापुर (बीपीटीपी), केवटी

162 करोड़ से अधिक की तेंदूपत्ता प्रोत्साहन राशि वितरण का शुभारंभ

सहकारिता से बढ़ेगी किसानों की आय, विकसित छत्तीसगढ़ की नींव होगी मजबूत : मुख्यमंत्री साय

1352 नई सहकारी समितियों के गठन से गांवों तक पहुंचा सहकार का विस्तार

उत्कृष्ट सहकारी समितियों को सहकार प्रेरणा पुरस्कार से किया गया सम्मानित

महिला स्व सहायता समूह को वितरित किया गया लाभांश

रायपुर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय का गठन देश के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय है। यह निर्णय सहकार से समृद्धि के संकल्प को साकार करने वाला है। डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में सहकारिता के माध्यम से किसानों, वनवासियों, महिला समूहों और ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने तथा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मंडपम में भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के पांच वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन एवं सहकारी सप्ताह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर उत्कृष्ट समितियों को सहकार प्रेरणा पुरस्कार प्रदान किया तथा संग्रहण वर्ष 2023 के 7.14 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए 162 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि के वितरण का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं और बचपन से ही सहकारिता से मेरा गहरा रिश्ता रहा है। तभी से मुझे विश्वास था कि सहकारिता के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि का वही सपना धरातल पर साकार होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रथम कार्यकाल में उन्हें राज्यमंत्री के रूप में साथ काम करने का अवसर मिला और उन्होंने किसानों के प्रति प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता तथा समर्पण को बहुत करीब से देखा है। किसानों के कल्याण के प्रति इसी प्रतिबद्धता के कारण प्रधानमंत्री ने कृषि मंत्रालय का दायरा बढ़ाते हुए उसका नाम %कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय% किया, ताकि किसानों का समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता बने। सहकारिता किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता का सबसे प्रभावी माध्यम बन रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा मिली है और इसका लाभ सीधे किसानों एवं ग्रामीण परिवारों तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि केंद्र सरकार केवल कृषि ही नहीं बल्कि पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, वनोपज, मत्स्य पालन और ग्रामीण उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में भी सहकारिता को मजबूत कर रही है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के सहयोग से प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में व्यापक बदलाव दिखाई देने लगे हैं। राज्य सरकार पशुपालन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पहले किसानों को खेती-किसानी के लिए 16 से 18 प्रतिशत दर पर ऋण लेना पड़ता था और भारी-भरकम ब्याज का बोझ उन्हें आर्थिक रूप से परेशान कर देता था। आज सहकारिता व्यवस्था और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से किसानों को बिना ब्याज ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रदेश के 15 लाख से अधिक किसानों को 8 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है, जिससे किसानों को खेती के लिए सुलभ वित्तीय सहायता मिल रही है और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जिस प्रकार दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व और सुरक्षा बलों के साहस से नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक सफलता मिली है, उसी प्रकार सहकारिता के माध्यम से भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन लाया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सहकारी सप्ताह के दौरान विषय विशेषज्ञों के मंथन से प्रदेश में सहकारिता के नए आयाम स्थापित होंगे और इसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से गंभीर श्वसन रोग से पीड़ित मासूम को मिली 95,500 रुपये की स्वास्थ्य सहायता

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशील पहल से गंभीर श्वसन रोग से पीड़ित सरगुजा जिले की मासूम रेणुका खलखो के उपचार का रास्ता आसान हो गया है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया में परिजनों द्वारा सहायता के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने मामले पर तत्काल संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके फलस्वरूप मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत उपचार के लिए 95 हजार 500 रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अनुशंसा पर राज्य नोडल एजेंसी द्वारा जारी स्वीकृति आदेश के अनुसार यह राशि झारखंड के रांची स्थित रानी हॉस्पिटल में मासूम के श्वसन संबंधी गंभीर बीमारी के उपचार के लिए प्रदान की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लिए यह सहायता बड़ी राहत लेकर आई है। समय पर मिली आर्थिक मदद से अब रेणुका का बेहतर उपचार संभव हो सकेगा। परिजनों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस सहयोग से उन्हें अपनी बच्ची के इलाज की नई उम्मीद मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना गंभीर एवं आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए जीवनरक्षक सहायता का प्रभावी माध्यम बन रही है। इस योजना के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों को समय पर आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे उपचार में आर्थिक बाधाएं दूर हो रही हैं।

मदरसा बोर्ड खत्म करने सीएम साय को डॉ राज ने लिखा पत्र

रायपुर। राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डा सलीम राज ने सीएम विष्णु देव साय को एक पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ में मदरसा बोर्ड खत्म करने की मांग की है। इसमें उन्होंने मदरसा बोर्ड की जगह राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन करने का सुझाव दिया है। ऐसा करने से मदरसे में अध्ययन रत छात्र आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मदरसों का पाठ्यक्रम तय करने कमेटी गठित की जाए जो धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक विषयों के साथ नया पाठ्यक्रम तैयार करे।डा राज ने कहा कि उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के तहत प्राधिकरण गठित किया गया है।

17 जजों का ट्रांसफर : अजय सिंह संभालेंगे एचसी की कमान

बिलासपुर. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग के न्यायिक अधिकारियों को तबादला आदेश जारी किया है. इस आदेश में 17 उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों को तबादला किया गया है. हाईकोर्ट से जारी आदेश में जगदलपुर में प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत को स्पेशल जज एनआईए कोर्ट जगदलपुर में पदस्थ किया गया है.

सिद्धार्थ अग्रवाल द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदलपुर को प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदलपुर, किरन कुमार जांगड़े को प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलरामपुर-रामानुजगंज, विनय कुमार प्रधान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी पाक्सों रायपुर को रायपुर में ही एफटीसी कोर्ट में पदस्थ किया गया है. डमरूधर चौहान षष्ठम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रायपुर को दसम जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद रायपुर में ही पदस्थ किया गया है. इस प्रकार बलौदाबाजार के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी का तबादला हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार विजलेंस के पद में किया गया है. बलौदाबाजार के प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार वर्मा का छत्तीसगढ़ न्यायिक अकादमी बिलासपुर में एडिशनल डायरेक्टर के पद में तबादला किया गया. हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के सचिव ओम प्रकाश जायसवाल को हाईकोर्ट में ही रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल के पद में पदस्थ किया गया है. रूपनारायण पात्रे द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर को हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी हाईकोर्ट में सचिव के पद में पदस्थ किया गया है.

रायपुर में अष्टविनायक रियल्टीज़ के आवास मेले के पहले दिन उमड़ी भारी भीड़

रायपुर। रायपुर के प्रतिष्ठित रियल एस्टेट डेवलपर अष्टविनायक रियल्टीज़ और अभिनव बिल्डर्स द्वारा मोवा, दलदल सिवनी स्थित बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट अभिनव सिटी में आयोजित तीन-दिवसीय भव्य आवास मेले का आज शानदार आगाज़ हुआ। 3 जुलाई को मेले के पहले ही दिन शहरवासियों का भारी उत्साह और अभूतपूर्व रिस्पॉन्स देखने को मिला। प्रकृति और आधुनिकता के संगम पर आधारित इस प्रोजेक्ट को ग्राहकों और निवेशकों द्वारा काफी सराहा जा रहा है। विजिटर्स और बुकिंग्स आयोजकों के अनुसार, मेले के पहले दिन लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। आज आवास मेले में लगभग 150 से अधिक विजिटर्स ने प्रोजेक्ट का भ्रमण किया। ग्राहकों के इस अपार उत्साह के चलते पहले ही दिन 27 से अधिक शानदार बुकिंग्स दर्ज की गईं, जो अभिनव सिटी की लोकप्रियता और डेवलपर्स के प्रति लोगों के अटूट भरोसे को दर्शाता है। सुविधाओं और लोकेशन का आकर्षण मेले में आए ग्राहकों ने विशेष रूप से प्रीमियम प्लॉट्स (गार्डन फेसिंग और कॉर्नर) तथा 2 व 3 बीएचके लग्ज़री अपार्टमेंट्स में गहरी दिलचस्पी दिखाई। विजिटर्स ने प्रोजेक्ट की प्राइम लोकेशन, विशेषकर अंबुजा मॉल, साइंस सेंटर और बालाजी हॉस्पिटल से इसकी नजदीकी की काफी सराहना की। इसके अलावा, 10 विशाल गार्डन्स, भव्य मंदिर, अत्याधुनिक जिम, स्विमिंग पूल, और मिनी थिएटर जैसी विश्वस्तरीय सुविधाओं ने हर उम्र के लोगों को आकर्षित किया। पहले दिन मिले इस शानदार रिस्पॉन्स पर खुशी ज़ाहिर करते हुए अष्टविनायक रियल्टीज़ के सीएमडी, श्री संतोष लोहाना ने कहा, मेले के पहले दिन शहरवासियों से मिला यह भारी समर्थन हमारे उस विज़न की जीत है, जिसके तहत हम ग्राहकों को सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि एक संपूर्ण और सुरक्षित जीवनशैली प्रदान करना चाहते हैं। हम सभी विजिटर्स के हृदय से आभारी हैं। वहीं, अष्टविनायक रियल्टीज़ के एमडी, श्री प्रकाश लोहाना ने कहा, आज का उत्साह यह साबित करता है कि अभिनव सिटी अपनी पारदर्शिता, लोकेशन और सुविधाओं के कारण रायपुर का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। जो लोग आज नहीं आ पाए, हम उन्हें आने वाले दो दिनों में आमंत्रित करते हैं। 4 और 5 जुलाई को भी जारी रहेगा मेला यह भव्य आवास मेला आगामी 4 और 5 जुलाई को भी जारी रहेगा। आयोजकों ने शहरवासियों से अपील की है कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और अपने सपनों का घर बुक करें।

सभी प्रमुख कार्यों की जिम्मेदारी अभियंताओं को सौंपी गई; हर बुधवार प्रगति रिपोर्ट अपडेट करना होगा

रायपुर नगर निगम के 70 वार्डों में नए वार्ड प्रभारी नियुक्त, आयुक्त संबित मिश्रा का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

रायपुर। निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने प्रशासनिक व्यवस्था के तहत सभी 70 वार्डों के लिये अभियंताओं को समस्त निर्माण कार्य, नगर निवेश के कार्य सहित अन्य सभी आवश्यक कार्यों के लिए वार्ड प्रभारी नियुक्त कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार वार्ड प्रभारी नगर निगम जोन 1 वार्ड 3 मो इम्तियाज अहमद उप अभियंता, वार्ड 4 गोपाल प्रधान उप अभियंता, वार्ड 5 राजेश पटेल उप अभियंता, वार्ड 15 श्रीमती किस्टमणी अनुकंपा बाडा सहायक अभियंता, वार्ड 16 शरद देशमुख सहायक अभियंता, वार्ड 17 सुश्री रश्मि भौसला उप अभियंता, वार्ड 18 श्रीमती अंकिता सोनवर्षा उप अभियंता, जोन 2 वार्ड 6 सुधीर भट्ट उप अभियंता, वार्ड 13 श्रीमती अंजली बारले उप अभियंता, वार्ड 14 अनिमेष चन्द्राकर उप अभियंता वार्ड 26 शुभम तिवारी उप अभियंता, वार्ड 27 गोविन्द साहेब बंजारे सहायक अभियंता, वार्ड 28 विजय शर्मा सहा. राज. अधिकारी वार्ड 35 पवन कश्यप राजस्व निरीक्षक, जोन 3 वार्ड 12 सत्यप्रकाश सिंह उप अभियंता वार्ड 29 जयनंदन डहरिया उप अभियंता, वार्ड 30 अक्षय भारद्वाज उप अभियंता, वार्ड 31 व 33 नरेश कुमार साहू प्र. सहायक अभियंता, वार्ड 47 श्रीमती श्रुति चतुर्वेदी उप अभियंता वार्ड 48 श्रीमती पूनम साहू उप अभियंता, जोन 4 वार्ड 34 हिमांशु चंद्राकर उप अभियंता वार्ड 43 श्रीमती अंकिता अग्रवाल उप अभियंता, वार्ड 44 व 45 दीपक देवांगन सहायक अभियंता, वार्ड 46 सुश्री राखी देवांगन उप अभियंता, वार्ड 57 गुलाब चंद कर्ष सहायक अभियंता, वार्ड 64 रोशनदेव रात्रे उप अभियंता जोन 5 वार्ड 39 सुश्री प्राची चौबे उप अभियंता, वार्ड 40 टिकेन्द्र चंद्राकर उप अभियंता, वार्ड 41 नागरेश्वर राव रामटेके सहायक अभियंता वार्ड 42 श्रीमती कृति शर्मा उप अभियंता, वार्ड 66 निर्मल तिग्गा उप अभियंता वार्ड 67 सुश्री मनीषा निराला उप अभियंता, वार्ड 68 अरविंद राहुल सहायक अभियंता, जोन 6 वार्ड 58 श्रीमती विद्या देशलहरा उप अभियंता, वार्ड 59 राजकमल धृतलहरे उप अभियंता, वार्ड 60 पुकेश साहू सहायक अभियंता वार्ड 61 सागर ठाकुर उप अभियंता, वार्ड 62 कनिका ढारगावे उप अभियंता, वार्ड 63 आशीष श्रीवास्तव प्र. सहायक अभियंता, वार्ड 65 अंकुर अग्रवाल सहायक अभियंता, जोन 7 वार्ड 22 सुरेंद्र श्रीवास उप अभियंता वार्ड 23 सुश्री रचना संघवी उप अभियंता, वार्ड 24 व 25 कमलेश मिथलेश सहायक अभियंता, वार्ड 36 शत्रुधन देशलहरे सहायक अभियंता, वार्ड 37 चन्द्रकांत बर्गे उप अभियंता, वार्ड 38 श्रीमती प्रेरणा अग्रवाल उप अभियंता, जोन 8 वार्ड 1 अंकुर मिश्रा उप अभियंता, वार्ड 2 अनुराग पाटकर सहायक अभियंता, वार्ड 19 अबरार खान उप अभियंता, वार्ड 20 लोचन प्रसाद चौहान उप अभियंता वार्ड 21 भुपेन्द्र डिल्ली उप अभियंता, वार्ड 69 अमन चंद्राकर सहायक अभियंता, वार्ड 70 योगेन्द्र साहू उप अभियंता जोन 9 वार्ड 7 अतुल बंसल उप अभियंता, वार्ड 8 आशुतोष पाण्डेय उप अभियंता, वार्ड 9 श्रीमती अंकिता जनार्दन उप अभियंता, वार्ड 10 सैय्यद जोहेब सहायक अभियंता, वार्ड 11 श्रीमती जिज्ञासा जैन उप अभियंता, वार्ड 32 कृष्णा साहू उप अभियंता, वार्ड 51 रविप्रभात साहू उप अभियंता जोन 10 वार्ड 49 फराज फारूकी प्र. सहायक अभियंता, वार्ड 50 राहुल थरानी उप अभियंता, वार्ड 52 नवीन वर्मा उप अभियंता, वार्ड 53 मनोज साहू सहायक अभियंता, वार्ड 54 श्रीमती निवृत्ति परमार उप अभियंता, वार्ड 55 मो. वसीम खान उप अभियंता, वार्ड 56 सुशील अहीर सहायक अभियंता नियुक्त किया गया है। वार्ड प्रभारी उन्हें सौंपे गये मूल कार्यों के अतिरिक्त ये कार्य भी करेंगे समस्त निर्माण कार्य, नगर निवेश के कार्य, वैध, अवैध होर्डिंग्स के सर्वे का कार्य, विद्युत संधारण, पाईप लाईन संधारण, पॉवर पंप संधारण, गार्डन का रख-रखाव, प्रधानमंत्री आवास निर्माण किये जाने बाबत् बी.एल.सी. एवं ए.एच.पी. आवास निर्माण हेतु कच्चे मकान का पात्र हितग्राहियों का सर्वे कार्य, ओपन स्पेस का सर्वे, वैध नल कनेक्शन।

शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण नीति पर हाईकोर्ट की मुहर, 24 से अधिक याचिकाएं खारिज

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और शालाओं के युक्तियुक्तकरण की नीति पर हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी है। इस नीति को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ विद्यालयीन शिक्षक कर्मचारी संघ सहित प्रदेशभर के शिक्षकों की सभी 24 से अधिक याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस बिभू दत्त गुरु की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा, कि शिक्षकों का स्कूलों में तर्कहीन या असमान वितरण सुधारने के लिए सरकार का यह कदम जनहित में है। बता दें, प्रदेश के ग्रामीण और अंदरूनी क्षेत्रों के शिक्षक विहीन या एकल-शिक्षकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। इसलिए 16,165 शिक्षकों एवं प्राचार्यों का युक्तियुक्तकरण किया गया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत राज्य की कुल 10463 शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया गया है। इनमें मुख्य रूप से एक ही परिसर में संचालित हो रहे 10297 स्कूल शामिल हैं। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा, ट्रांसफर और पोस्टिंग पूरी तरह से सरकार के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र का हिस्सा हैं और किसी भी सरकारी कर्मचारी को एक ही जगह जमे रहने का कोई संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ छत्तीसगढ़ विद्यालयीन शिक्षक कर्मचारी संघ सहित प्रदेशभर के शिक्षकों की सभी 24 से अधिक याचिकाओं को खारिज कर दिया।

विश्वकप से बाहर हुई सेनेगल टीम में उभरे मतभेद

न्यूजर्सी। फीफा विश्वकप फुटबॉल से बाहर होने के बाद सेनेगल टीम में मतभेद खुलकर सामने आ गये हैं। यहां तक कि स्टार मिडफील्डर पापे गुए ने टीम से अनिश्चितकालीन समय तक बाहर रहने की घोषणा कर दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक मौजूदा तकनीकी स्टाफ टीम के साथ रहेगा, वह सेनेगल की जर्सी नहीं पहनेंगे। यह सब राउंड ऑफ-32 के उस बेहद रोमांचक मुकाबले के बाद हुआ, जहां सेनेगल का सामना बेल्जियम से था। मैच के 51वें मिनट तक सेनेगल ने 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली थी पर बाद में उसे 3-2 से हार का सामना करना पड़ा था।

गुए की नाराजगी का एक बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है कि उन्हें मैच के लगभग एक घंटे बाद कोच पापे थियाव ने मैदान से बाहर बुलाकर उनकी जगह लमीन कामारा को उतारा था, वही खिलाड़ी जिसने बाद में निर्णायक पेनाल्टी के लिए फाउल किया। इस हार के तुरंत बाद, पापे गुए ने सोशल मीडिया पर अपनी गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, मैं बाद में इस हार पर विस्तार से बात करूंगा, लेकिन फिलहाल इतना कह रहा हूं कि जब तक यही तकनीकी स्टाफ टीम के साथ रहेगा, मैं राष्ट्रीय टीम से ब्रेक ले रहा हूं। उनका यह बयान टीम में गहरे मतभेद का संकेत दे रहा है और सवाल उठा रहा है कि क्या यह हार केवल एक खेल का नतीजा थी या इसमें रणनीतिक गलतियाँ भी शामिल थीं।

हालांकि सेनेगल वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, लेकिन पूरे टूनार्मेंट में पापे गुए का व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। उन्होंने अपनी टीम के लिए तीन महत्वपूर्ण गोल किए और एक असिस्ट भी दिया। इराक के खिलाफ 5-0 की शानदार जीत में उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था, जो उनके फॉर्म और टीम के लिए उनके महत्व को दर्शाता है। एक व्यक्तिगत रूप से सफल प्रदर्शन के बाद टीम से ब्रेक लेने का उनका फैसला उनके असंतोष की गहराई को उजागर करता है। इस नाटकीय विदाई के बावजूद, सेनेगल ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। टीम एक ही फीफा वर्ल्ड कप संस्करण में 10 गोल करने वाली पहली अफ्रीकी टीम बनकर उभरी है, जो उनकी आक्रामक खेल शैली का प्रमाण है। अब देखना यह है कि पापे गुए के इस फैसले के बाद सेनेगल फुटबॉल फेडरेशन क्या कदम उठाता है

16वां डीजीसी जूनियर/सब-जूनियर गोल्फ टूनार्मेंट 7 जुलाई से शुरू होगा

नई दिल्ली। भारतीय गोल्फरों को नया अवसर प्रदान करने के लिए 16वां डीजीसी जूनियर/सब-जूनियर गोल्फ टूनार्मेंट 2026, 7 से 9 जुलाई तक प्रतिष्ठित दिल्ली गोल्फ क्लब में आयोजित किया जा रहा है। उषा द्वारा आयोजित यह तीन दिवसीय भव्य आयोजन, देश भर से युवा और उभरते हुए गोल्फरों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने और प्रतिस्पर्धा के उच्च स्तर का अनुभव करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। यह टूनार्मेंट न केवल खेल कौशल को निखारने का एक मंच है, बल्कि युवाओं को खेलों में निवेश के महत्व को भी मजबूती से रेखांकित करता है, जिससे नई पीढ़ी के उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रेरणा और दिशा मिलती है।

यह टूनार्मेंट केवल एक प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि भारतीय गोल्फ के लिए नर्सरी के रूप में कार्य करता है। यह उन युवा खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है जो पेशेवर गोल्फ की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य युवा प्रतिभाओं को प्रारंभिक अवस्था में पहचानना, उन्हें सही मार्गदर्शन और विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करके उनके कौशल को निखारना है। पिछले कुछ वर्षों में, इस टूनार्मेंट ने कई ऐसे सितारों को जन्म दिया है जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जिससे इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। यहां से निकले खिलाड़ी अक्सर बड़े आयोजनों में भारत का

झंडा बुलंद करते हैं, जिससे देश में गोल्फ के प्रति उत्साह और जुड़ाव बढ़ता है।

दिल्ली गोल्फ क्लब, जो अपनी हरी-भरी फेयरवे और चुनौतीपूर्ण कोर्स के लिए जाना जाता है, इस प्रतिष्ठित आयोजन के लिए एक आदर्श स्थान है। यह क्लब भारतीय गोल्फ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है और इसने अनगिनत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूनार्मेंटों की मेजबानी की है। युवा गोल्फरों के लिए ऐसे ऐतिहासिक और विश्व स्तरीय कोर्स पर खेलने का अनुभव अमूल्य होता है। यह उन्हें बड़े टूनार्मेंटों के दबाव को संभालने और अपनी खेल रणनीति को बेहतर बनाने का अवसर देता है। क्लब का वातावरण और सुविधाएं युवा खिलाड़ियों को अपने सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे वे अपनी सीमाओं को पार कर सकें।

टूनार्मेंट में विभिन्न आयु वर्गों के जूनियर और सब-जूनियर खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि हर उम्र के प्रतिभाशाली बच्चे अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकें और अपने समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। इन युवा गोल्फरों को न केवल प्रतिस्पर्धा का मौका मिलेगा, बल्कि वे एक-दूसरे से सीख भी पाएंगे और खेल भावना को मजबूत करेंगे। ऐसे आयोजनों से ही भविष्य के ओलंपिक पदक विजेता और प्रमुख टूर पेशेवर सामने आते हैं, जो देश का नाम रोशन करते हैं। यह भारतीय गोल्फ पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और भविष्य के लिए एक मजबूत प्रतिभा पूल बनाने में मदद करता है। टूनार्मेंट का उद्घाटन 7 जुलाई को एक शानदार समारोह के साथ होगा, जिसमें खेल जगत की कई हस्तियां और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। तीन दिनों की कड़ी प्रतिस्पर्धा और बेहतरीन खेल कौशल के प्रदर्शन के बाद, 9 जुलाई को एक भव्य पुरस्कार वितरण समारोह के साथ टूनार्मेंट का समापन होगा।

फीफा विश्व कप 2026 के दौरान सोशल मीडिया पर अभद्रता के मामले बढ़े

अटलांटा। अमेरिका, कनाडा और मैक्सको में खेले जा रहे विश्ककप फुटबॉल मुकाबलों के दौरान सोशल मीडिया पर अभद्रता की घटनाएं भी तेजी से बढ़ी हैं और ये पिछले विश्वकप से अधिक हैं। विश्व फुटबॉल की शीर्ष संस्था (फीफा) ने ये खुलासा किया है। फीफा के अनुसार ग्रुप स्तर के मुकाबलों के दौरान ही सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की संख्या में काफी तेजी आई है। संगठन की डिजिटल मॉनिटरिंग टीम ने कुल 89,000 ऐसे पोस्ट की पहचान की है, जो 2022 कतर विश्व कप की तुलना में 13 गुना अधिक हैं। इस दौरान नस्लीय टिप्पणियों में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है, और 100 से अधिक मामलों में कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है।

ये आपत्तिजनक पोस्ट मुख्य रूप से खिलाड़ियों, भाग लेने वाली टीमों और मैच अधिकारियों को निशाना बनाकर की गई थीं। फीफा के सोशल मीडिया प्रोटेक्शन सर्विस (एसएमपीएस) ने इस विशाल डेटा का विश्लेषण किया। 2026 विश्व कप के ग्रुप स्टेज के दौरान, एसएमपीएस ने 60 लाख से अधिक सोशल मीडिया पोस्ट और कमेंट्स की निगरानी की, जो 2022 विश्व कप के मुकाबले 33 फीसदी ज्यादा हैं।

विश्लेषण में सामने आया कि इन पोस्ट्स में से 11 फीसदी सीधे तौर पर नस्लीय दुर्व्यवहार से संबंधित थीं। फीफा ने चिंता व्यक्त की है कि नस्लीय टिप्पणी और भेदभावपूर्ण पोस्ट का अनुपात 2022 विश्व कप की तुलना में तीन प्रतिशत बढ़ गया है, जिसे संगठन ने सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली सबसे गंभीर और आपत्तिजनक सामग्री में खतरनाक वृद्धि बताया है। फीफा ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया प्रोटेक्शन सर्विस (एसएमपीएस) का उद्देश्य सभी भाग लेने वाली टीमों, खिलाड़ियों, कोचों और मैच अधिकारियों को सोशल मीडिया पर होने वाले नस्लीय, भेदभावपूर्ण और धमकी भरे संदेशों से बचाना है। फीफा ने इस बढ़ोतरी का एक प्रमुख कारण विश्व कप में टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 करना बताया है, जिसके परिणामस्वरूप सोशल मीडिया गतिविधियों और विश्लेषण किए गए कंटेंट की मात्रा में स्वाभाविक रूप से वृद्धि हुई है।

टी20 प्रारुप क्रिकेट का भविष्य, एकदिवसीय का आकर्षण घट रहा: अश्विन

चेन्नई। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कहा है कि वर्तमान हालातों में जहां टी20 प्रारुप लगातार आगे बढ़ रहा है। वहीं एकदिवसीय प्रारुप का अस्तित्व संकट में नजर आ रहा है। अश्विन के अनुसार लगातार नई लीग शुरू होने से साफ है कि टी20 का भविष्य उज्वल है और इसमें काफी अवसर हैं। अश्विन ने कहा कि फ्रेंचाइजी आधारित यूरोपीय टी20 प्रीमियर लीग (ईटीपीए) से भी कई देशों तक क्रिकेट फैल रहा है। इसके अलावा साल 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में भी क्रिकेट की वापसी से टी20 प्रारुप को दुनिया भर में विकसित होने का अवसर मिलेगा।

अश्विन ने विशेष रूप से टी20 प्रारूप की अपील और पहुंच पर जोर दिया। उनका तर्क है कि छोटा प्रारूप दर्शकों को त्वरित मनोरंजन प्रदान करता है और दुनिया भर में तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा, टी20 क्रिकेट का भविष्य बेहद मजबूत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके विपरीत, जब बात एकदिवसीय क्रिकेट की आती है, तो इसका आकर्षण घट रहा है। उन्होंने कहा कि वह इस प्रारूप के दीर्घकालिक भविष्य को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हैं, खासकर आधुनिक क्रिकेट कैलेंडर में इसकी जगह को लेकर।

अश्विन के अनुसार ईटीपीएल जैसे आयोजन विभिन्न देशों के उभरते और स्थापित खिलाड़ियों को एक मंच पर लाते हैं, जिससे खेल का स्तर और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। यह लीग यूरोप में क्रिकेट की पहुंच को मजबूत करेगी, एक ऐसा क्षेत्र जहां क्रिकेट अभी भी फुटबॉल जैसे खेलों की तुलना में अपनी जगह बना रहा है। अश्विन के अनुसार, यह सिर्फ एक और लीग नहीं, बल्कि खेल के भविष्य के लिए एक रणनीतिक कदम है।

इस दिग्गज स्पिनर की प्रेम कहानी है फिल्मी...सबसे खूबसूरत पारी की शुरूआ हुई

चंड़ीगढ़। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह का जीवन उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। मैदान पर अपनी जादुई स्पिन से दुनिया के बड़े-बड़े बल्लेबाजों के होश उड़ाने वाले भज्जी जब खुद प्यार के जाल में फंसे, तो उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पारी की शुरूआत हुई। यह कहानी है हौसलों की उड़ान, मैदान के आक्रामक तेवरों और फिर पहली ही नजर में बॉलीवुड की एक हसीना पर क्लीन बोल्ड हो जाने की। हरभजन की प्रेम कहानी पूरी तरह से फिल्मी और लव एट फर्स्ट साइट का बेहतरीन उदाहरण है। बात उन दिनों की है जब भज्जी लंदन में थे। एक दिन उन्होंने टीवी पर फिल्म द ट्रेन का सुपरहिट गाना वो अजनबी देखा। गाने में नजर आ रही अभिनेत्री गीता बसरा की खूबसूरती पर भज्जी इस कदर फिदा हुए कि उन्होंने तुरंत ठान लिया कि वे इस लड़की से मिलकर रहेंगे। उन्होंने अपने खास दोस्त और साथी क्रिकेटर युवराज सिंह को फोन मिलाया और गीता के बारे में पूछताछ की। आखिरकार, बॉलीवुड के गलियारों में अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर भज्जी गीता का फोन नंबर हासिल करने में कामयाब रहे। नंबर मिलते ही उन्होंने गीता को मैसेज कर कॉफी पीने का न्योता दे दिया पर ब्रिटेन के पोर्ट्समाउथ में जन्मीं गीता ने शुरूआत में इस स्टार क्रिकेटर को कोई खास भाव नहीं दिया और उनके मैसेज का कोई जवाब नहीं आया।

इस एकतरफा लव स्टोरी में ट्विस्ट तब आया जब टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनी। इस ऐतिहासिक जीत के बाद गीता ने खुद

हरभजन को फोन करके बधाई दी। यहीं से दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद भज्जी ने गीता को आईपीएल मैच देखने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन गीता नहीं आईं, जिससे भज्जी का दिल टूट गया। धीरे-धीरे दोस्ती गहरी हुई और जब हरभजन ने पहली बार गीता को प्रपोज किया, तो गीता ने अपने बॉलीवुड करियर का हवाला देते हुए साफ इनकार कर दिया। लेकिन भज्जी भी अपनी जिद के पक्के थे। वे पीछे नहीं हटे और आखिरकार करीब 7 साल की लंबी डेटिंग के बाद अक्टूबर 2015 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। आज इस कपल के दो प्यारे बच्चे हैं- बेटी हिनाया हीर और बेटा जोवन वीर सिंह।

जिस दौरान हरभजन और गीता के बीच यह नजदीकियां बढ़ रही थीं, ठीक उसी दौर में मैदान पर हरभजन सिंह का नाम भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े विवादों से जुड़ रहा था। गीता बसरा ने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि भज्जी बाहर से जितने कड़क और सख्त दिखते हैं, दिल से उतने ही नरम हैं। लेकिन मैदान पर उनका यह कड़क अंदाज कई बार बड़े तूफानों की वजह बना। साल 2008 की ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान सिडनी टेस्ट में हरभजन सिंह और ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स के बीच तीखी बहस हुई थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भज्जी पर नस्लीय टिप्पणी (ह्यमंकीह्व कहने) का आरोप लगाया, जिसने इतना तूल पकड़ा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट संबंध दांव पर लग गए थे और भज्जी को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित भी किया गया।

कारोबार

शाओमी कर रही अगली शाओमी 18 सीरीज पर काम

नई दिल्ली। शाओमी अपनी अगली फ्लैगशिप शाओमी 18 सीरीज पर काम कर रही है। लेटेस्ट लीक्स के मुताबिक, शाओमी 18 में पिछले मॉडल की तुलना में बड़ी बैटरी मिलेगी, साथ ही 200 मेगापिक्सल का कैमरा और 2के डिस्प्ले जैसे प्रीमियम फीचर्स भी शामिल होंगे। जाने-माने चीनी टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन के अनुसार, शाओमी 18 के इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप में 7,200 एमएएच की बैटरी दी गई है। अगर यह जानकारी सही साबित होती है, तो यह शाओमी 17 में दी गई 7,000 एमएएच की बैटरी से 200 एमएएच अधिक होगी।

शाओमी का लक्ष्य कॉम्पैक्ट डिजाइन बनाए रखते हुए बैटरी क्षमता बढ़ाना है। डिस्प्ले की बात करें तो, इसमें 6.4 इंच का 2के डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जिसमें 19.5:9 आस्पेक्ट रेशियो और पतले बेजेल्स होंगे, जिससे फोन का डिजाइन प्रीमियम दिखेगा। फोटोग्राफी के लिए, फोन में 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया जा सकता है, जिसमें 1/1.28-इंच का बड़ा सेंसर होगा।

कुछ रिपोर्ट्स यह भी संकेत देती हैं कि शाओमी 18 सीरीज के कुछ मॉडल्स में डुअल 200 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप भी देखने को मिल सकता है, जो कैमरा लवर्स के लिए एक बड़ी बात होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाओमी 18 सीरीज को चीन में सितंबर में लॉन्च किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे पिछले साल शाओमी 17 सीरीज लॉन्च हुई थी। उस सीरीज में शाओमी 17, शाओमी 17 प्रो और शाओमी 17 प्रो मैक्स शामिल थे।

घटकर 60 डॉलर तक आ सकता है कच्चा तेल भारतीय कंपनियों को होगा फायदा

होर्मुज से आवाजाही शुरू होने से घटी चिंता

नई दिल्ली। होर्मुज के आसपास तनाव कम होने से कच्चे तेल की आपूर्ति से जुड़ी चिंताएं लगभग खत्म हो गई हैं। इसके अलावा, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के निर्यात को सामान्य दरों की ओर बढ़ाने से क्रूड की कीमतों में गिरावट और गहरी हो गई है।

चीन की कमजोर मांग और आपूर्ति में वृद्धि से अब बाजार में सप्लाई सरप्लस की संभावना बढ़ गई है। इससे क्रूड में और गिरावट की उम्मीद बढ़ गई है।

सिटीग्रुप ने एक रिपोर्ट में कहा, भू-राजनीतिक तनाव कम होने से ब्रेंट क्रूड ने युद्ध के दौरान हुई अपनी सारी बढ़त को गंवा दी है और इसमें 30 फीसदी की गिरावट देखी गई।

हालात सामान्य होने की स्थिति में ब्रेंट क्रूड के दाम इस साल के अंत तक गिरकर 60 डॉलर प्रति बैरल तक आ सकते हैं। इस राहत से भारत की सरकारी तेल कंपनियों को घाटे की भरपाई करने में मदद मिलेगी, जिन्हें 30 जून तक 74,781 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। सरकार भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत देने पर विचार कर सकती है।

खाड़ी देशों से निर्यात युद्ध-पूर्व स्तर का 90% पहुंचा

सऊदी अरब पिछले हफ्ते के अंत में अपने विशाल रास तनुरा टर्मिनल से शिपमेंट को फिर से शुरू करने के बाद पिछले स्तर के करीब 90 फीसदी पर कच्चे तेल को लोड करने में कामयाब रहा। सऊदी अरब की यह वापसी उसके पड़ोसी देश संयुक्त अरब अमीरात जैसी ही है, जिसने पिछले महीने अपने तेल निर्यात को युद्ध-पूर्व स्तर यानी 39 लाख बैरल प्रतिदिन से अधिक पर बहाल कर दिया था। अनुमान है कि होर्मुज के रास्ते अब तेल आपूर्ति एक करोड़ बैरल प्रतिदिन से अधिक हो गई है। इससे बाजार में तेल की बाढ़ आ गई है। वह भी ऐसे समय जब युद्ध के समय अपनाए कई वैकल्पिक उपाय अब भी लागू हैं। मॉर्गन स्टेनली ने भी हाल के सप्ताहों में कच्चे तेल के मूल्य के अपने अनुमानों में दो बार कटौती की है और उभरते हुए आपूर्ति अधिशेष की चेतावनी दी है।

ऊर्जा बाजार में धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं हालात

होर्मुज के जरिये आवागमन फिर से शुरू होने के साथ वैश्विक ऊर्जा बाजार धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं। इससे निकट अवधि में तेल की आपूर्ति में सुधार हुआ है, जो संघर्ष के दौरान रिफाइनरियों की ओर से वैकल्पिक स्रोतों को सुरक्षित करने की आपाधापी के बाद बड़ी राहत है।

कमजोर मानसून से बिगड़ सकता है आम आदमी का बजट

इस साल 6 फीसदी रहेगी खाद्य महंगाई

नई दिल्ली। इस साल आम आदमी की थाली का बजट और बिगड़ सकता है। रेटिंग एजेंसी केयरएज रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2026-27 में देश में औसत खाद्य महंगाई बढ़कर 6 फीसदी के आसपास रह सकती है, जबकि खुदरा महंगाई दर 5 फीसदी पर टिक सकती है। इस चिंता की बड़ी वजह मानसून की शुरूआत में हुई कम बारिश है, जिससे खेती-किसानी और फसलों के उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका है।

रिपोर्ट के मुताबिक, एक से 30 जून के बीच देश में सामान्य से 40 फीसदी कम बारिश हुई है। इस भारी कमी ने सरकार और आम आदमी दोनों की चिंता बढ़ा दी है। मई में पहले ही खाद्य तेल की महंगाई दर 9.5 फीसदी के उच्च स्तर पर थी। ऐसे में कमजोर मानसून खाद्य पदार्थों की कीमतों को और भड़का सकता है।

जुलाई में भी कम बारिश

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि जुलाई में मानूसन की बारिश लंबी अवधि के औसत के 94 फीसदी से कम हो सकती है। इससे कृषि उत्पादन एवं फसलों की पैदावार को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं। भारत के कृषि क्षेत्र में सालाना होने वाली कुल बारिश का लगभग 70 फीसदी हिस्सा दक्षिण-पश्चिम मानसून से ही आता है।

जून सबसे सूखे महीनों में

भारत में 1901 के बाद से इस बार जून पांचवां सबसे सूखा महीना दर्ज किया गया है, जहां बारिश सामान्य से 40 फीसदी कम रही। मौसम विभाग ने पहले जून में मानसून की बारिश लंबी अवधि के औसत के 92 फीसदी से कम रहने की भविष्यवाणी की थी। आईएमडी के अनुसार, देश के मध्य, पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों के बड़े इलाकों में औसत से कम बारिश होने का अनुमान है।

गेमर्स के लिए खुशखबरी! भारतीय स्टार्टअप ने खोली नए हैंडहेल्ड गेमिंग डिवाइस की प्रतीक्षा सूची

नई दिल्ली। भारतीय गेमिंग हार्डवेयर कंपनी एआरसी ने आधिकारिक तौर पर अपने पहले हैंडहेल्ड गेमिंग डिवाइस के लिए प्रतीक्षा सूची खोल दी है। पंजीकरण प्रक्रिया उपयोगकताओं को उत्पाद अपडेट, लॉन्च घोषणाएं और डिवाइस की आधिकारिक रिलीज तक प्राथमिकता खरीद के अवसर प्राप्त करने की अनुमति देती है। कंपनी ने कहा कि इस विकास का उद्देश्य भारतीय बाजार में अंतराल को संबोधित करना है, जहां प्रीमियम हैंडहेल्ड गेमिंग हार्डवेयर तक पहुंच ऐतिहासिक रूप से उच्च लागत और घरेलू उपभोक्ताओं के बजाय वैश्विक पर ध्यान केंद्रित करने के कारण सीमित रही है।

सह-संस्थापक जोबिन जोसेफ के अनुसार, वेटलिस्ट का उद्देश्य गेमर्स को प्लेटफॉर्म के केंद्र में अपनी प्रतिक्रिया देकर विकास प्रक्रिया में शामिल करना है। हार्डवेयर से परे, एआरसी एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर रहा है जिसमें एक मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर सेवाएं और एक समुदाय के नेतृत्व वाला प्लेटफॉर्म शामिल है। सह-संस्थापक कौस्तुभ के. जाधव ने कहा कि कंपनी लॉन्च से पहले उपयोगकर्ता अनुभव को परिष्कृत करने के लिए शुरूआती अपनाने वालों, रचनाकारों और डेवलपर्स के साथ सहयोग करने का इरादा रखती है। जैसे ही कंपनी बाजार में प्रवेश की तैयारी कर रही है, वह प्रतीक्षासूची वाले उपयोगकताओं को विकास अंतर्दृष्टि और अपडेट प्रदान करने की योजना बना रही है। प्रतीक्षा सूची के लिए पंजीकरण वर्तमान में कंपनी की वेबसाइट पर खुले हैं।

महत्वपूर्ण ख़बर

सड़क दुर्घटना में घायल 04 व्यक्तियों को त्वरित सहायता देकर पहुँचाया अस्पताल

■ भोपाल। भिंड जिले के थाना मेहगाँव क्षेत्र में डायल-112 जवानों की तत्परता एवं संवेदनशील कार्यवाही से देर रात सड़क दुर्घटना में घायल हुए 04 व्यक्तियों को समय पर अस्पताल पहुँचाकर उपचार उपलब्ध कराया गया। डायल-112 टीम की त्वरित सहायता से सभी घायलों को शीघ्र चिकित्सकीय सुविधा मिल सकी।

03 जुलाई को राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल-112 भोपाल में सूचना प्राप्त हुई कि थाना मेहगाँव क्षेत्र अंतर्गत एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई है, जिससे उसमें सवार कुछ व्यक्ति घायल हो गए है। पुलिस सहायता की आवश्यकता है। सूचना प्राप्त होते ही थाना मेहगाँव क्षेत्र में तैनात डायल-112 वाहन को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया।

मध्यप्रदेश के लिए रूपए 5,00,856 करोड़ की वार्षिक ऋण योजना 2026-27 जारी

■ भोपाल। मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने मंत्रालय में शुक्रवार को वित्त विभाग के अधिकारियों और राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी के समन्वयक से कहा है कि वे जिलों से प्राप्त जिला स्तरीय क्रेडिट प्लान का हर हाल में क्रियान्वयन कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ बनाएं। मुख्य सचिव श्री जैन ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा प्रस्तुत वार्षिक साख योजना 2026-27 का विमोचन कर जारी की। विमोचन के दौरान अपर मुख्य सचिव वित्त श्री मनीष रस्तोगी, आयुक्त संस्थागत वित्त सुश्री सोनिया मीना, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक सुश्री सुजाता लाल, उपमहाप्रबंधक नाबार्ड श्री विजेंद्र सिंह, उपमहाप्रबंधक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति श्री पवन कुमार अग्रवाल, भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक श्री निशंका रॉय सहित अन्य बैंक के अधिकारी उपस्थित हुये।

खेती की लागत कम करना और किसानों की आय बढ़ाना हमारी प्राथमिकता

किसानों से सीधे संवाद के लिए राजधानी से लेकर मैदानी स्तर तक किये जाये कार्यक्रम आयोजित: मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों का कल्याण राज्य सरकार का कर्तव्य है। खेती की लागत कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए गतिविधियों को प्राथमिकता पर लिया जाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया गया है।

कृषकों के हित संवर्धन के लिए लागू कार्यक्रमों और योजनाओं का क्रियान्वयन मिशन मोड में किया जाए। किसानों से सीधे संवाद के लिए राजधानी से लेकर मैदानी स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। दुग्ध उत्पादन किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष रूप से सहायक है। किसानों को उन्नत नस्ल की गाय उपलब्ध कराने में निजी संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाए। ग्रामीण स्तर पर इस तरह के केन्द्रों का अधिक से अधिक विस्तार हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत अब तक हुए कार्यक्रमों की मंत्रालय में समीक्षा कर रहे थे। बैठक में आगामी प्रस्तावित कार्यक्रमों के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बैठक में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सहकारी समितियों की प्रक्रियाओं का डिजिटलाइजेशन हो

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों को कम पानी और अल्प अवधि की फसलों के लिए जागरूक किया जाए। फसल चक्र में परिवर्तन और प्राकृतिक व जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए वातावरण बनाना आवश्यक है। खेती-किसानी से जुड़े स्थानीय पर्व और त्यौहारों तथा फसल चक्र के अनुसार किसानों से संवाद स्थापित किया जाए। सुगमता और सरलता सुनिश्चित करते हुए सहकारी समितियों की प्रक्रियाओं का डिजिटलाइजेशन किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में जानकारी दी गई कि ऑनलाईन किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल और किसानों के लिए ई-पासबुक सुविधा का शुभारंभ जुलाई माह में ही किया जाएगा। राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन भी होगा। उत्कृष्ट कार्य करने वाले मैदानी कार्यकताओं तथा पशुपालकों को पुरस्कृत और सम्मानित करने के लिए उज्जैन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्रदेश के सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किए जाएंगे और सभी संभागीय मुख्यालयों पर फूड फेस्टिवल होंगे।

बैठक में बताया गया कि खरगौन में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन और कपास एवं मिर्च महोत्सव के आयोजन की योजना है। अन्तर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि पर जबलपुर में कार्यक्रम होगा। इसी प्रकार जबलपुर में ही कुक्कुट पालकों और उद्यमियों का सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। बुरहानपुर में केला महोत्सव, उज्जैन में हाईटेक नर्सरी और संरक्षित खेती पर कार्यशाला, सागर और रतलाम में कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का राज्य स्तरीय सम्मेलन, नीमच में उद्यानिकी में आधुनिक तकनीक पर कार्यशाला, इंदौर में सब्जी महोत्सव तथा एक्वाकल्चर मार्केटिंग सिम्पोजियम और भोपाल पराली प्रबंधन पर कार्यशाला के साथ ही नरसिंहपुर में गन्ना महोत्सव के अंतर्गत राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन भी प्रस्तावित है। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री के.सी गुप्ता, श्री नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव श्री डी.पी. आहूजा, श्री उमाकांत उमराव, आयुक्त जनसम्पर्क श्री मनीष सिंह उपस्थित थे।

वर्षा के मौसम में सावधानी रखने की अपील

बालाघाट में बाढ़ में फंसे ग्रामीणों के लिए मध्यप्रदेश पुलिस बनी जीवनरक्षक

भोपाल। प्रदेश में लगातार हो रही वर्षा के बीच मध्यप्रदेश पुलिस आपदा की प्रत्येक स्थिति में आमजन की सुरक्षा के लिए पूरी संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में बालाघाट जिले के थाना किरनापुर क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में फंसे 16 ग्रामीणों का पुलिस, एसडीआरएफ एवं हॉक फोर्स के संयुक्त अभियान के माध्यम से सफलतापूर्वक सुरक्षित रेस्क्यू किया गया।

लगातार हो रही मूसलाधार वर्षा के कारण थाना किरनापुर क्षेत्र के ग्राम भानपुर में खेतों पर कृषि कार्य करने गए लगभग 16 ग्रामीण अचानक बढ़ते जलस्तर के कारण चारों ओर से बाढ़ के पानी में घिर गए। नदी-नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ने से उनके वापस लौटने का मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया और सभी ग्रामीण बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में फंस गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना

किरनापुर पुलिस ने बिना विलंब किए थाना हट्टा पुलिस, राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) एवं हॉक फोर्स की टीम के साथ संयुक्त रेस्क्यू अभियान प्रारंभ किया। तेज बहाव एवं विषम परिस्थितियों के बावजूद टीम ने साहस, सूझबूझ और उत्कृष्ट समन्वय का परिचय देते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र तक पहुंचकर सभी 16 ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाला तथा सकुशल सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। समय पर की गई त्वरित कार्रवाई के कारण किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

जनसुरक्षा के लिए मध्यप्रदेश पुलिस की अपील

मध्यप्रदेश पुलिस ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि लगातार वर्षा के दौरान नदी-नालों, पुल-पुलियों एवं जलमग्न मार्गों को पार करने का प्रयास न करें। खेतों अथवा अन्य स्थानों पर जाने से पूर्व मौसम एवं जलस्तर की जानकारी अवश्य प्राप्त करें तथा प्रशासन एवं पुलिस द्वारा जारी सुरक्षा संबंधी निदेशों का पूर्णत: पालन करें। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस द्वारा आवश्यक बैरिकेड एवं सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।

आमजन से अनुरोध है कि प्रतिबंधित मार्गों से आवागमन न करें तथा किसी भी आपातकालीन स्थिति में तत्काल डायल-112 अथवा निकटतम पुलिस थाने को सूचना दें। मध्यप्रदेश पुलिस प्रदेशवासियों की सुरक्षा के लिए 24*7 सतर्क एवं प्रतिबद्ध है तथा किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्यरत है।

सांदीपनि विद्यालयों का लोकार्पण बने आनंदोत्सव

हर विद्यार्थी की हो सहभागिता : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

नवनिर्मित 70 सांदीपनि विद्यालयों का 15 जुलाई तक करायें लोकार्पण

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को मंत्रालय प्रदेश के सभी नवनिर्मित सांदीपनि विद्यालयों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन विद्यालयों का लोकार्पण औपचारिक कार्यक्रम न होकर शिक्षा, संस्कृति और जनभागीदारी का सामाजिक उत्सव बने। उन्होंने कहा कि वर्तमान में संचालित 'स्कूल चलें अभियान' के दौरान आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों तथा स्थानीय नागरिकों की व्यापक सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सांदीपनि विद्यालयों का लोकार्पण आनंद के उत्सव के रूप में मनाया जाए। यह नए भवनों के उद्घाटन के साथ हमारे नौनिहालों के उज्ज्वल भविष्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए अध्याय का शुभारंभ है। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यक्रमों को यादगार बनाने के लिए बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न प्रतियोगिताएँ तथा अन्य रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की जाएँ। साथ ही सभी विद्यार्थियों को स्वल्पाहार एवं मिष्ठान्न वितरित किया जाए, जिससे यह अवसर उनके लिए अविस्मरणीय बन सके।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरु सांदीपनि के प्रेरणादायी जीवन पर आधारित एक लघु पुस्तिका (पॉकेट बुक) प्रकाशित कर विद्यार्थियों में वितरित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुरु सांदीपनि तत्समय सामाजिक समरसता के सबसे बड़े पैरोकार थे। उन्होंने जाति, वर्ग, रंग का भेद न करके अमीर-गरीब से लेकर राज परिवार के बच्चों सहित गरीबों और किसानों के बच्चों को शिक्षा-दीक्षा दी। सभी को समान रूप से दीक्षित किया। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में हम सबके विशेषकर विद्यार्थियों को जानना जरूरी है। इससे विद्यार्थियों को प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, गुरु-शिष्य संबंधों और नैतिक मूल्यों के बारे में जानकारी और प्रेरणा मिलेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिन सांदीपनि विद्यालयों का लोकार्पण पहले ही हो चुका है, वहाँ प्रवेशोत्सव उत्साहपूर्वक आयोजित किया जाए, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों का विद्यालयों से जुड़ाव बढ़े। उन्होंने अधिकारियों से सभी तैयारियाँ समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक सांदीपनि विद्यालय प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण, संस्कारयुक्त और आधुनिक शिक्षा का आदर्श केंद्र बने।

स्कूली वाहनों पर आरटीओ की सख्ती, नियम तोड़ने वाले 10 वाहन जब्त

इंदौर। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है।

कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर शुक्रवार को आरटीओ ने छोटा बांगड़दा क्षेत्र के स्कूल वाहनों की आकस्मिक जांच की। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 10 वाहनों को जब्त किया गया। इनमें तीन स्कूल बसें, तीन ट्रेवलर और चार मैजिक वाहन शामिल हैं।

जांच के दौरान वाहनों के परमिट, फिटनेस, बीमा सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। साथ ही वाहनों का भौतिक निरीक्षण कर फायर सेफ्टी उपकरण, स्पीड गवर्नर और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं का परीक्षण किया गया। आरटीओ अधिकारियों ने स्कूली बच्चों और अभिभावकों से भी फीडबैक लिया। इस दौरान वाहन चालकों द्वारा तेज गति से वाहन चलाने,

मोबाइल फोन का उपयोग करने और सुरक्षा नियमों के पालन से जुड़े पहलुओं की जानकारी भी जुटाई गई।

निरीक्षण में कई वाहन स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते नहीं पाए गए। वहीं तीन वाहनों के परमिट और फिटनेस प्रमाणपत्र की अवधि भी समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद मौके पर ही तीन बसों, तीन ट्रेवलर और चार मैजिक वाहनों को जब्त कर कार्रवाई की गई।

कार्रवाई के दौरान आरटीओ प्रदीप शर्मा, एआरटीओ अर्चना मिश्रा, आरटीओ कार्यालय का अमला और उड़नदस्ता दल मौजूद रहा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले के सभी स्कूलों और कॉलेजों के वाहनों की आकस्मिक जांच लगातार जारी रहेगी। शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि केवल फिट, वैध दस्तावेजों वाले और सभी सुरक्षा मानकों का पालन करने वाले वाहनों का ही संचालन किया जाए।

भारत और जर्मनी दो भाईयों की तरह: मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से शुक्रवार को जर्मनी के 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मंत्रालय में सौजन्य भेंट की। प्रतिनिधिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री से मध्यप्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल में जर्मनी के केएफडब्ल्यू डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी बोर्ड की सदस्या एवं बैंक की सीईओ सुश्री क्रिस्टियाने लाईबेक, कंट्री डायरेक्टर श्री वूल्फन मूथ, जर्मन दूतावास के प्रतिनिधि श्री गॉटफ्रीड वॉन और अन्य सदस्य, प्रबंध संचालक म.प्र. औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड श्री चंद्रमौली शुक्ला, श्री विशेष गढ़पाले सहित केन्द्र सरकार के अधिकारी भी उपस्थित थे।

मुख्यनमंत्री डॉ. यादव ने भारत एवं जर्मनी के बीच दशकों पुरानी मित्रता का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देश भाईयों की तरह हैं। इनमें आपसी साझेदारी को और अधिक प्रबल बनाने में मध्यप्रदेश बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। सरकार जर्मनी के उद्योगपतियों और निवेशकों से लगातार सम्पर्क में है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ऊर्जा क्षेत्र में केएफडब्ल्यू डेवलपमेंट बैंक के सहयोग की सराहना करते हुए आशा जताई कि हमारी साझेदारी दिन-ब-दिन और भी सुदृढ़ होगी। जर्मनी के सहयोग से हमारा मध्यप्रदेश एक ऊर्जा दक्ष हरित और समृद्ध राज्य बनेगा।

केएफडब्ल्यू बैंक के प्रतिनिधिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री डॉ. यादव को अवगत कराया गया कि एनर्जी रिफार्म प्रोग्राम अन्तर्गत वितरण कंपनियों में स्मार्ट मीटर की स्थापना एवं फीडर विभक्तिकरण कार्य के लिए लगभग 1120 करोड़ रुपए का वित्त पोषण किया जा रहा है। बैंक द्वारा इस साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए एनर्जी रिफार्म फेज-2 अंतर्गत प्रदेश में विद्युत वितरण अधोसंरचना निर्माण तथा सौर घंटों में कृषि फीडरों की आपूर्ति के लिये अधोसंरचनात्मक निर्माण कार्यों के लिए लगभग 200 मिलियन यूरो के वित्तीय सहयोग पर भी रूचि दिखाई है।

अब पॉवर जनरेटिंग कंपनी के कार्मिकों के घरों पर चमकेगी सौर ऊर्जा: ऊर्जा मंत्री

भोपाल। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड ने अपने कार्मिकों के लिए एक महत्वपूर्ण और दूरगामी पहल करते हुए सोलर रूफटॉप प्लांट योजना लागू की है। ऊर्जा विभाग के निदेर्शों के अनुरूप जारी इस योजना से कंपनी के सभी नियमित कार्मिकों को अपने आवास पर सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित कराने की सुविधा मिलेगी। अब इच्छुक कार्मिक प्रदेश की संबंधित विद्युत वितरण कंपनी (डिस्कॉम) की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और सूचीबद्ध विक्रेताओं में से अपनी पसंद के विक्रेता का चयन कर सोलर प्लांट स्थापित करा सकेंगे।

श्रीरामानुज संस्कृत परिसर वैदिक अध्ययन और शोध का बनेगा महत्वपूर्ण केंद्र : उप मुख्यमंत्री

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के श्रीरामानुज संस्कृत परिसर, लक्ष्मण बाग, रीवा के सशक्तीकरण एवं संस्थागत विकास संबंधी प्रस्तावों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि श्रीरामानुज संस्कृत परिसर संस्कृत, वैदिक अध्ययन, भारतीय दर्शन, प्राचीन शास्त्रों तथा भारतीय ज्ञान परम्परा के अध्ययन-अध्यापन और शोध का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। श्रीरामानुज संस्कृत परिसर, रीवा में अध्ययन-अध्यापन, शोध, प्रकाशन, परीक्षा, प्रशासनिक एवं विस्तार गतिविधियों के सुचारु संचालन के लिए शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। परिसर के लिए कुल 243 पदों के सृजन तथा उनकी पूर्ति तीन वर्षों में चरणबद्ध रूप से किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें 117 शैक्षणिक, 4 प्रशासनिक तथा 122 गैर-शैक्षणिक पद सम्मिलित हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन उपस्थित थे।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि परिसर में आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध होने से विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शोध मार्गदर्शन और आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। उन्होंने परिसर के संधारण एवं शैक्षणिक गतिविधियों के विस्तार के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि पदों की स्वीकृति से श्रीरामानुज संस्कृत परिसर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप शैक्षणिक वातावरण विकसित होगा। साथ ही संस्कृत भाषा, वैदिक ज्ञान, भारतीय दर्शन और पारम्परिक विद्या प्रणालियों के संरक्षण, संवर्धन एवं व्यापक प्रसार को नई गति मिलेगी। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि श्रीरामानुज संस्कृत परिसर, लक्ष्मण बाग, रीवा की स्थापना मध्यप्रदेश शासन द्वारा 5 अक्टूबर 2023 को की गई थी। परिसर में संस्कृत, वैदिक अध्ययन तथा भारतीय शास्त्रों एवं भारतीय ज्ञान परम्परा से संबंधित विषयों में अध्ययन-अध्यापन एवं शोध कार्य संचालित किए जा रहे हैं। वर्तमान में परिसर में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन सीमित संसाधनों से किया जा रहा है। परिसर में वेद, वेदान्त दर्शन, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, संस्कृत, योग, पुराणेतिहास, धर्मशास्त्र, वास्तुशास्त्र, संगीत, मानविकी, पौरोहित्य, हिन्दू अध्ययन, भारतीय ज्ञान परम्परा और शिक्षाशास्त्र सहित विभिन्न विभागों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव है।

विद्यार्थी हित, गुणवत्ता और पारदर्शिता पर आधारित कार्य संस्कृति विकसित करें विश्वविद्यालय

भोपाल। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने कहा कि विश्वविद्यालय केवल डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान नहीं, बल्कि ऐसे ज्ञान केंद्र हैं, जहाँ समाज की समस्याओं का समाधान करने वाले श्रेष्ठ, संवेदनशील, नैतिक एवं राष्ट्रनिष्ठ नागरिकों का निर्माण होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल रोजगार के योग्य बनाना नहीं, बल्कि उन्हें समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप सक्षम, उत्तरदायी एवं नवाचारी बनाना है। विश्वविद्यालयों को इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना होगा। मंत्री श्री परमार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल में आयोजित "शिक्षा संवाद" कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मंत्री श्री परमार ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य सभी विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक उत्कृष्टता, शोध, नवाचार, सुशासन एवं विद्यार्थी-केंद्रित व्यवस्था के आदर्श मॉडल के रूप में विकसित करना है। विश्वविद्यालयों की कार्य संस्कृति ऐसी होनी चाहिए, जिसमें प्रत्येक निर्णय विद्यार्थी हित, गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लिया जाए।उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय केवल ज्ञान प्रदान करने तक सीमित न रहें, बल्कि समाज को दिशा देने वाले सशक्त शैक्षणिक संस्थान बनें।

मंत्री श्री परमार ने कहा कि आदर्श विश्वविद्यालय वही है, जहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, समयबद्ध शैक्षणिक गतिविधियाँ, अनुशासित व्यवस्था, शोध की सशक्त संस्कृति, नवाचार तथा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों। विश्वविद्यालयों को ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए, जहाँ विद्यार्थी केवल डिग्री प्राप्त न करें, बल्कि समाज एवं राष्ट्र की चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करने वाले सक्षम नागरिक बनकर निकलें।

मंत्री श्री परमार ने कहा कि प्राध्यापकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए 'सार्थक ऐप' का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है, जिससे शिक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र से विद्यार्थियों की उपस्थिति भी 'सार्थक ऐप' के माध्यम से दर्ज की जायेगी, जिससे नियमित उपस्थिति, अनुशासन, कक्षाओं में सहभागिता तथा शिक्षण की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार आएगा। मंत्री श्री परमार ने कहा कि समय पर प्रवेश, समय पर परीक्षा और समय पर परिणाम, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की आधारशिला हैं। परीक्षा प्रणाली को पूर्णत: पारदर्शी, तकनीक आधारित एवं त्रुटिरहित बनाने के लिए डिजिटल मूल्यांकन, ऑनलाइन परीक्षा प्रबंधन तथा आधुनिक तकनीकों का अधिकतम उपयोग किया जाए।

संपादक: अली आदिल खान द्वारा सांई प्रिंटिंग प्रेस डी-85, न्यू अशोक अगर, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, यूपी से मुद्रित कराकर सी-148, साउथ मोती बाग,पो. चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 से प्रकाशित किया।
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।